www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 06 | गोरखपुर, 04 अगस्त 2024 रविवार | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 2

शांति वार्ता के बीच जिरीबाम में भड़क उठी ताजा हिंसा, जला दिया मैतई परिवार का घर

मणिपुर। जिरीबाम जिले में मैतेई और हमार समूहों द्वारा जिले में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयासों के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत के एक दिन बाद, शुक्रवार की रात आगजनी की एक ताजा घटना हुई जिसमें एक मैतेई परिवार का घर जला दिया गया। यह घटना जिरीबाम के लालपानी गांव में हुई, जो एक बंगाली बहुल इलाका है, जो सेजांग नामक कुकी गांव के करीब है। पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने इलाके में सुरक्षा खामियों का फायदा उठाया और परित्यक्त घर में आग लगाने से पहले गोलियां चलाईं।

एक अधिकारी ने बताया कि यह एक अलग बस्ती है जिसमें कुछ मैतेई घर शामिल हैं, और उनमें से अधिकांश को जिले में हिंसा भड़कने के बाद छोड़ दिया गया था। उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में सुरक्षा खामियों का फायदा उठाया।

अधिकारी ने बताया कि हथियारबंद बदमाशों ने, जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, गांव को निशाना बनाकर कई राउंड गोले दागे और गोलियां भी चलाईं।

घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया। जिरीबाम के एसपी एम प्रदीप सिंह ने कहा, ₹हमने सीआरपीएफ के साथ एक संयुक्त टीम भेजी थी। कुछ उकसावे की कार्रवाई हुई थी लेकिन हमने स्थिति को और अधिक भड़के बिना नियंत्रित कर लिया है। हम इस बात पर विचार करने के लिए बैठक कर रहे हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाए।₹ गुरुवार को, मैतेई और हमार समुदायों के प्रतिनिधियों ने असम के कछार से सटे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सुविधा में मुलाकात की और तीन प्रमुख प्रस्तावों पर एक समझौते पर पहुंचे।

▶ अवैध गतिविधियों के खिलाफ 'मैसूर चलो' पदयात्रा शुरू

एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

बेंगलुरू। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि राज्य में सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस शासित सरकार की कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ 10 दिवसीय ' मैसूर चलो' पदयात्रा शुरू की गई है। जेडीएस नेता ने कहा कि हम इस कार्यक्रम को मैसूरु में समाप्त करने जा रहे हैं।' यह इस (कांग्रेस) सरकार द्वारा की गई कई अवैध गतिविधियों के खिलाफ हैः भ्रष्टाचार, भूमि कब्जा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान वे कर्नाटक के लोगों को बताएंगे कि यह सरकार कैसे सत्ता में आई। उसके बाद, पहले दिन से, कैसे उन्होंने सरकारी खजाने से भी, यहां तक कि अधिकारियों से भी पैसा हड़पना शुरू कर दिया। एचडी कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि वे यह सब अवैध हस्तांतरण कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कैसे पैसा इकट्ठा किया है। हमने लोगों को इन सभी मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) के विपक्षी गठबंधन ने शनिवार को कथित एमयूडीए और वाल्मिकी निगम घोटालों को लेकर बेंगलुरु के केंगेरी से मैसूर तक अपनी 10 दिवसीय 'मैसूर चलो' पदयात्रा शुरू की। शुक्रवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कथित मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले को लेकर भाजपा की पदयात्रा की आलोचना की और कहा कि वे एक गैर-मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनसे पूछना चाहती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। यह भाजपा की अब तक की सबसे निंदनीय सरकार थी। वे बिना बात के पदयात्रा कर रहे हैं, वे गैर-मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल ने 27 जुलाई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे का दावा करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके बहनोई मलिकार्जुन स्वामी देवराज, जो एक जमींदार होने का दावा करते थे, और उनके परिवार पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी शिकायत में कई सवाल उठाए हैं।

दो भारतीय दलालों सहित 6 बांग्लादेशी नागरिकों किया गिरफ्तार

अगरतल्ला। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवानों ने गुरुवार को अगरतला रेलवे स्टेशन से अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में आठ बांग्लादेशी नागरिकों और दो भारतीय दलालों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को राज्य से बाहर पश्चिम बंगाल, चेन्नई और तमिलनाडु की ओर जाने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था। मीडिया से बात करते हुए, जीआरपी के अगरतला रेलवे स्टेशन प्रभारी तापस दास ने कहा कि आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया है और विदेशी अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। आगे की पूछताछ के लिए आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की याचिका दायर की गई। बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान शहादत हुसैन, त्रिशा अख्तर, शापला अख्तर, राजू अहमद, शाह आलम, शुकुर्जी, बिप्लब और करीम सेन के रूप में की गई है। भारतीय दलालों की पहचान रतन पॉल और शुक्ला सरकार के रूप में की गई है। ये गिरफ्तारियां अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले छह बांग्लादेशी नागरिकों को अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम (एमबीबी) हवाई अड्डे से गुरुवार को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद हुई हैं। पिछले कुछ महीनों में अगरतला रेलवे स्टेशन और त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जब वे राज्य से बाहर ट्रेनों या वाहनों में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। विदेशी नागरिकों की घुसपैठ में वृद्धि के साथ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने जुलाई में सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उनसे कड़ी निगरानी बनाए रखने को कहा था। उन्होंने बीएसएफ से बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने में मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा। बीएसएफ ने संवेदनशील सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी है और दलालों और तस्करों के नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं। इसने त्रिपुरा में बांग्लादेशी नागरिकों की आमद और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए तस्करी विरोधी अभियान भी तेज कर दिया है।

नकारात्मक राजनीति की पीठ पर सवार विपक्ष

एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितनी जरूरत एक सशक्त सरकार की होती है, उतना ही सशक्त विपक्ष भी जरूरी होता है। विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के प्रकटीकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु, वर्तमान में भारत का विपक्ष झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति में गले तक डूबा दिखाई देता है।

एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष एक निगरानीकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न विचारों को व्यक्त करने, समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में सहायक होता है।

एक दशक तक लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त रहा, क्योंकि सदन में किसी भी पार्टी के पास सदन की कुल सदस्य संख्या के दसवें हिस्से के बराबर सदस्य नहीं थे, जो अब रायबरेली के सांसद राहुल गांधी द्वारा भरा गया है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता संसदीय सीमाओं, अनुशासन, परंपराओं और कर्तव्यों की लक्ष्मण रेखा प्रतिदिन लांघ रहे हैं।

राहुल गांधी संसद में खड़े होकर जो मन में आता है, बोलते हैं। उनके भाषण का कोई सिरा आपस में जुड़ता नहीं है। असल में वो रटी रटाई स्क्रिप्ट को सदन में दोहराते हैं। वो सरकार पर निशाना साधने और उस-की साख को गिराने के एजेंडे को हर दिन आगे बढ़ाते हैं। चुनाव नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी के संसद में दिये गये भाषणों और मीडिया के सामने की गयी बयानबाजी का विश्लेषण करें तो वो सीधे तौर पर देश के हर तबके और वर्ग में असंतोष पैदा करने में जुटे हैं। वो मोदी सरकार की साख पर बट्टा लगाने के मिशन में जुटे हैं। विपक्ष के नेता और विपक्ष की भूमिका के इतर वो हर वो काम कर रहे हैं, जो विशुद्ध तौर पर राजनीति का हिस्सा है।

संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की जांच करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, भारत में 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विपक्ष द्वारा निभाई गई भूमिका ने भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दों को उजागर किया। विपक्ष नीतिगत मामलों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। 2013 में विपक्ष के रूप में भाजपा ने तत्कालीन यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रभावी ढंग से आलोचना की, जिससे उसे महत्वपूर्ण चुनावी लाभ हुआ।

वहीं विपक्ष विविध और अल्पसंख्यक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे बहुलवादी समाज सुनिश्चित होता है। डीएमके और एआईटीसी जैसी क्ष-त्रीय पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सबके अलावा विपक्ष विधायी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अक्सर कानूनों में सुधार होता है। मौजूदा सरकार के तहत जीएसटी विधेयक में विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधन इसका एक उदाहरण हैं।

1960 के दशक के आरंभ से भूमि सुधार, औद्योगिक मजदूर वर्ग के अधिकार, बेरोजगारी, खाद्यान्न एवं उनका वितरण, जातीय मांगों और भाषाई अधिकारों जैसे विभिन्न मुद्दों पर पूरे भारत में शक्तिशाली आंदोलनों की शुरूआत हुई। तत्कालीन विपक्ष ने स्वयं को इन सामाजिक आंदोलनों से उल्लेखनीय रूप से संलग्न किया था। इतिहास में संसदीय विपक्ष ने भारत के संसदीय लोकतंत्र को रचनात्मकता और सकारात्मकता प्रदान की थी। वहीं इस बात में दो राय नहीं है कि कमजोर विपक्ष एक कमजोर या गैर-उत्तरदायी सरकार से कहीं अधिक खतरनाक होता है। और एक गैर-उत्तरदायी, अनुशासहीन और संसदीय परंपराओं को न मानने वाला विपक्ष देश को तबाही की रास्ते पर ले जाता है।

4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष ने इंडी गठबंधन के बैनर तले मोदी सरकार को हर छोटे–बड़े मुद्दे पर घेर रहा है। खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस संसदीय नियमों, लोकतंत्र की मयार्दाओं और परंपराओं को भूलकर लगातार तीन लोकसभा चुनाव में मिली हार की खीझ उतारती दिख रही है।

पिछले तीन आम चुनाव में ये तो साबित हो चुका है कि सीधी लड़ाई में विपक्ष मोदी को शिकस्त देने में सक्षम नहीं है। विपक्ष के झूठ, दुष्प्रचार और गलत बयानबाजी के बावजूद देश के हर वर्ग का विश्वास मोदी के प्रति कायम है। ऐसे में इंडी गठबंधन ने झूठ, दुष्प्रचार और विवादित मुद्दे उछालने की रणनीति पर काम करना शुरू कर रखा है।

2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने दुष्प्रचार और झूठ का सहारा लिया है। मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। भोली भाली जनता विपक्ष के दुष्प्रचार के दुष्चक्र में फंसी भी। इस चुनाव में विपक्ष की सीटें 2014 और 2019 के चुनाव की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई। विपक्ष के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में सबसे ज्यादा 240 सीटें डाली। जमीनी सच्चाई यह है कि तीसरी बार कांग्रेस विपक्ष में बैठने को मजबूर है। देश की जनता ने उसे सत्ता के लायक नहीं समझा। इस चुनाव में झूठ, षडयंत्र, दुष्प्रचार और पूरी ताकत लगाने के बावजूद विपक्ष सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाया। लगातार तीन चुनाव में हार की खीझ, झुंझलाहट, हताशा और निराशा विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी में साफ तौर पर झलकती है।

विशेषकर गांधी की गतिविधियां, भाषण और बयानबाजी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी कभी अग्निवीर और नीट परीक्षा की आड़ में युवाओं को, कभी किसानों को, कभी अल्पसंख्यक समुदायों को, कभी सरकारी कर्मचारियों को, कभी दलित और आदिवासियों के मन में सरकार, संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्था के प्रति रोष, असंतोष और घृणा भरने का काम कर रहे हैं। वो तो देश की जनता इतनी परिपक्व और समझदार है कि वो इनके कुत्सित इरादों ओर नीयत को समझती है। अगर जनता की समझदारी में थोड़ी भी कमी या अपरिपक्वता होती तो चार जून के बाद से अब तक देश में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं घट गयी होती। देश में अशांति, असुरक्षा और भय का वातावरण बन गया होता। देश की समझदार और परिपक्व जनता इस समझदारी, धैर्य और अनुशासन के लिये बधाई की पात्र है। राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने और आगे बढ़ाने के लिये विरोधी दल की आलोचना करते हैं। ये आम बात है। लेकिन विरोध नीतियों, नीयत और निर्णयों पर होना चाहिए। वहीं विरोध और आलोचना में सत्य, प्रामाणिकता और सकारात्मकता होनी चाहिए। आधे अधूरे तथ्यों, जानकारी और आंकड़ों के आधार पर एक दूसरे की आलोचना करना एक स्वस्थ लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले एक दशक से विपक्ष झूठ, दुष्प्रचार, फेक न्यूज फैलाने और झूठे नैरेटिव गढ़ने में व्यस्त है। उसके पास देश की समस्याओं के समाधान की कोई कार्ययोजना और नीति नहीं है। देश के विकास और जनकल्याण का कोई मॉडल और विजन उसके पास नहीं है। विपक्ष झूठ के सहारे सत्ता हासिल करना चाहता है। और देशवासियों की समस्याओं के समाधान के तौर पर रेवड़ी कल्चर का पिटारा उसके पास है।

लोकतंत्र का स्वास्थ्य प्रायः उसके विपक्ष की ताकत और जीवंतता में झलकता है। भारत में विपक्ष को मजबूत करना सिर्फ.राजनीतिक दलों को सशक्त बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के बारे में भी है। राज्य द्वारा वित्त पोषण, मीडिया तक समान पहुंच और पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। एक जीवंत, उत्तरदायी और जवाबदेह लोकतंत्र के लिए एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष आवश्यक है। वर्तमान में विपक्ष अपनी भूमिका, कर्तव्यपालन और उत्तरदायित्व के पालने में असफल दिखाई देता है। विपक्ष को झूठ, दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति छोड़कर देश और जनता के हित, कल्याण, समृद्धि और विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसी में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों की भलाई और कल्याण निहित है।

जून-जुलाई में हुई जमकर बारिश

खड्डा, कुशीनगर (जीकेबी)। खड्डा तहसील क्षेत्र में जून व जुलाई में इस साल जमकर बारिश हुई है। पंद्रह वर्ष बाद इस जुलाई में 600 मिली मीटर से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले वर्ष बरसात के चार महीनों में कुल 1187 मिमी बारिश के सापेक्ष इस वर्ष डेढ़ माह में ही 774 एमएम बारिश हो चुकी है। क्षेत्र में दो व तीन जुलाई को दो दिन में ही 338 एमएम बारिश हुई थी। नेपाल में बारिश ने गंडक नदी में बाढ़ ला दिया और जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। कई गांवों में पानी भर गया, लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी।

नेपाल से निकली गंडक नदी खड्डा क्षेत्र में बहती है। इसके सटे बिहार का 885 वर्ग किमी में फैला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल एवं महराजगंज जनपद का सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य है। नेपाल का चितवन नेशनल प्राणी उद्यान भी ज्यादा दूर नहीं है। मानसून के समय हर वर्ष बारिश का उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। किसी वर्ष अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है तो किसी सूखा पड़ जाता है। वर्ष 2003 के जुलाई माह में 849.6 एमएम, वर्ष 2007 मे 963.0 एमएम, वर्ष 2008 में 604.8 एमएम बारिश हुई थी। इसके बाद जुलाई में बारिश कम होती रही, वर्ष 2017 में मात्र 166 एमएम वर्षा रिकॉर्ड हुई थी।

इस वर्ष 15 जून से बरसात का सीजन शुरू होते ही बारिश ने जोर पकड़ लिया। इस वर्ष जून में 162.0 एमएम, जुलाई में 612 एमएम वर्षा हो चुकी है। शुरूआती डेढ माह में ही 774 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई है। जबकि पिछले वर्ष जून में 90 एमएम, जुलाई में 309 एमएम बारिश हुई थी। पिछले वर्ष चार माह में कुल 1187 एमएम बारिश हुई थी। वर्ष 2009 के जून में मात्र 16 एमएम, वर्ष 2010 के जून में 65.8 एमएम, 2017 में 65 एमएम, 2020 में 68.03 एमएम व पिछले वर्ष 2023 में मात्र 90 एमएम वर्षा हुई थी। परंतु 2006 जून में 514 एमएम, 2021 के जून में 415.8 एमएम बारिश हुई थी।

नेपाल में जबरदस्त बारिश से गंडक में आई थी बाढ़

इस वर्ष नेपाल में जबरदस्त बारिश के चलते गंडक नदी में बाढ़ आ गई। नदी खतरे के निशान 96.00 मीटर से 22 सेमी ऊपर पहुंच गई।

बाढ़ प्रभावित मरचहवा, बसंतपुर, शिवपुर, हरिहरपुर, नरायनपुर, विंध्याचल पुर, सालिकपुर, महदेवा आदि गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। जबकि पिछले वर्ष बाढ़ नहीं थी। चक्रवाती तूफान ने केला किसानों की कमर तोड़ दी तो सैकड़ों पेड़ व घर धराशायी हो गए। कई दिनों तक विद्युत सप्लाई ठप रही। हर वर्ष बरसात में लोगों को अलग-अलग तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है।

जुलाई में हुई बारिश-2001 --494.6 मिमी, 2002 --374.8 मिमी, 2003 --849.6 मिमी, 2004 --307.4 मिमी, 2005 --403.0 मिमी, 2006 --359.0 मिमी, 2007 --963.0 मिमी, 2008 --604.8 मिमी, 2009 --426.8 मिमी, 2010 --376.2 मिमी, 2011 --383.0 मिमी, 2012 --428.8 मिमी, 2013 --227.2 मिमी, 2014 --358.0 मिमी, 2015 --269.6 मिमी, 2016 --304.6 मिमी, 2017 --166.0 मिमी, 2018 --401.0 मिमी, 2019 --415.4 मिमी, 2020 --441.4 मिमी, 2021 --475.0 मिमी, 2022 --315.8 मिमी, 2023 --309.0 मिमी, 2024 --612.0 मिमी।

जून माह में हुई बारिश- 2001 --177.0 मिमी, 2002 --278.8 मिमी, 2003 --348.0 मिमी, 2004 --223.4 मिमी, 2005 --106.4 मिमी, 2006 --514.4 मिमी, 2007 --189.6 मिमी, 2008 --367.0 मिमी 2009 -- 16.0 मिमी, 2010 -- 65.8 मिमी, 2011 --117.6 मिमी, 2012 --131.4 मिमी, 2013 --383.6 मिमी, 2014 --256.0 मिमी, 2015 --230.6 मिमी, 2016 --222.0 मिमी, 2017 -- 65.0 मिमी, 2018 --110.2 मिमी, 2019 --167.4 मिमी, 2020 -- 68.3 मिमी, 2021--415.8 मिमी, 2022 --172.0 मिमी, 2023----90.0 मिमी, 2024--163.0 मिमी।

स्रोत-केंद्रीय जल आयोग।

घूँघट की बगावत

04 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू का जन्म हुआ था। वह एक निडर और निष्कपट महिला थी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अपने पति पंडित नेहरू का खूब साथ दिया कई आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया उनकी सौम्यता और विनम्रता के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा।

स्वाधीनता आंदोलन के तूफान में अपनी छाप छोड़ने वाली कमला नेहरू

कमला नेहरू का जन्म दिल्ली के व्यापारी पंडित जवाहरलाल माल और राजपति कॉल के घर एक अगस्त 1899 को एक परंपरावादी हिंदू परिवार में कश्मीरी ब्राह्मण के यहां हुआ। परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में पाली बड़ी होने के कारण हिंदू संस्कार उनके चरित्र का अहम हिस्सा थे वह एक शांत और शमीर्ली लड़की थी उनकी शिक्षा घर पर हुई थी और शादी के पहले इनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। सर्व विदित है कि 17 वर्ष की उम्र में कमला नेहरू का पंडित जवाहरलाल नेहरू से विवाह हो गया था कमला नेहरू दिल्ली के परंपरा आबादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी लेकिन शादी के बाद पश्चिमी परिवेश वाले नेहरू खानदान में इनको एकदम अलग माहौल मिला जिसके कारण वह खुद को अलग-अलग महसूस करती थीं । शादी के बाद कमला नेहरू ने एक बेटी इंदिरा को जन्म दिया फिर उन्होंने बेटे को जन्म दिया लेकिन वह कुछ दिनों के बाद ही इस दुनिया से चल बसा। शादी के बाद उनको स्वाधीनता संग्राम को समझने और नजदीकी से समझने का पूरा मौका मिला क्योंकि ससुर मोतीलाल नेहरू और पति जवाहरलाल नेहरू आंदोलन में सक्रिय थे जब तक कमला नेहरू जीवित रही वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। 1921 में कमला नेहरू ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और इलाहाबाद में महिलाओं के समूह को गठित की उन्होंने विदेशी वस्त्र तथा शराब की बिक्री करने वाली दुकानों का घेराव किया। कमला नेहरू का गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देखने को उसे वक्त मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को सरकार विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नी कमला नेहरू ने आगे बढ़कर पति के भाषण को पूरा किया अंग्रेजी सरकार ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनकी गतिविधियों के लिए कमला नेहरू को दो बार गिरफ्तार भी किया। साल 2019 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया। अपने निडर और निष्कपट स्वभाव के कारण पंडित नेहरू के लक्षण को भली-भांति समझती और उनकी मदद भी करती थीं।भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान कमला नेहरू लंबे समय तक गांधी आश्रम में रही और इसी दौरान महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के संपर्क में वह आएंगे और उनकी मित्रता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभादेवी से हो गई थी। अपने आखिरी समय में कमला नेहरू टीवी से पीड़ित हो गई इस दौरान यह एक खतरनाक बीमारी थी कमला नेहरू को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाया किया लेकिन इसके बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और 28 फरवरी 1936 को कमला नेहरू ने स्विट्जरलैंड के लोजान शहर में अंतिम सांस ली ।

सामाजिक ध्रुवीकरण का हथियार-जाति

जातीय या धार्मिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है न कि नकारात्मक तौर पर । क्योंकि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जाति और धर्म को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतर्विरोधाभासो से भरे पड़े हैं । वैदिक या सनातन सभ्यता- संसकति में जो जाति कार्यकुशल जनसमूह की कार्यदक्षता की निशानी समझी जाती थी और राष्ट्रीय उत्पादकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आई थी, वही जब लोकतात्रिक या सवैधानिक सभ्यता-संस्कृत में व्यापक विवाद का वाहक बनकर दिन- प्रतिदिन अनुत्पाद के प्रतीत होने लगे, तो देश व समाज के प्रबद्ध लोगों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। इसलिए आज संसद में जाति के सवाल पर भाजपा नीत एनडीए और काग्रेस नीत इंडिया ब्लॉक के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसके पीछे के राजनीतिक मायने को समझने और आमलोगों को समझआाने की जरूरत है।

पहला, चूकि राजनीतिक दलों के लिए जाति अब सामाजिक ध्रवीकरण का औजार और सियासी गोलबंदी का हथियार बन चुरकी है, इसलिए उसे सकारात्मक नजरिए से देखे जाने की जरूरत है, न कि नकारात्मक तरीके से। हां, अब जाति के परिप्रेक्ष्य में वह मुद्दा उठाने की जरूरत है जिससे राजनीतिक दल और उसके चतुर सुजान नेता अब तक बचते आए हैं। जैसे- साधुओं की जाति, वर्णसंकर लोगों की जाति और अंतरधार्मिक विवाह रचाने वाले लोगों और उनकी संततियों के धर्म का मुद्दा आदि सबसे अहम है।

दूसरा, जातीय या धामिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है, न कि नकारात्मक तौर पर। क्योंकि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जाति और धर्म को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतर्विरोधाभाषों से भरे पड़े हैं। जिसकी वजह से उनमें स्पष्टता का अभाव तो है। लोकतंत्र की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी नदारत है। इस स्थिति के लिए हमारे राजनेता और नौकर- शाह दोनों ही जिम्मेदार हैं लेकिन इस स्थिति को बदलने का साहस किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखा, जिससे राष्ट्रीयहित और पेशेवर गुणवत्ता गहरे तक प्रभावित होती आई है जिससे वैश्विक मुकाबले में भारत पिछडता चला आया। तीसरा, जाति और धर्म के आधार पर बने कानूनों में व्याप्त विसंगतियों और इससे प्रभावित हो रहे सामान्य जनजीवन के खिलाफ स्वतः संज्ञान न लेकर न्यायविदों ने भी 'कालीदासी विद्वत्ता' का ही परिचय दिया है। जिस देश में वह लोकतात्क न्याय दे रहे हैं।

वहीं पर जव कानूनी व न्यायिक प्रावधान व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की पारस्परिक भावना को मुँह चिढाने लगे, तो समझा जा सकता है कि मत समानता रहने के बावजूद पीडित व प्रभावित व्यक्ति कितना असहाय महसूस कर रहा होगा। खास बात यह कि इस देश में जाति और जातीय आरक्षण की जो अवधारणा तय की गई है. सवर्ण-पिछड़ा- दलित- आदिवासी और उनकी गरीबी के अलावा अल्पसंख्यक- बहुसख्यक के जो मानदंड तय किये गए हैं, वो ताकि कम, प्रतिशोधी ज्यादा प्रतीत होते हैं । लेकिन क्या मजाल कि कोई इन्हें गलत उहरा दे या उन्में संशोधन की बात करे। इससे तो यही लगता है कि संविधान निभाताओं से लेकर संविधान के कथित संरक्षकों और संसद में पिछले लगभग 8 दशक से बैठ रहे अधिकाश माननीयों ने जनतात्रिक कुएं में पड़ी भांग पी ली है जिन्हें तर्क और तथ्य से कोई वास्ता नहीं, बस पददलित जनमानस पर निरंतर विहसते जा रहे है।

चतुर्थ बस यही हाल राष्ट्र में जनमत निर्धारण करने में अमूल्यें सहयोग देने वाली समग्र मीडिया इकाइयों और उसके अदूरदर्शी सम्पादकों का भी है, जिन्होंने बस्तुनिष्ठ पत्रकारिता की बजाय पक्षधरता भरी रिपोर्टिंग की और नीर- क्षीर विवेक वाक विद्या वको सियासतदानों के मन के मुताबिक जैसे-तैसे परिभाषित किया। इससे जहां जनता गफलत में रही, वहीं संवैधानिक सिपहसालार मजे में परंतु कोढ़ में खाज यह कि जाति/ सम्प्रदाय जैसे जनहित के मुद्दे जहा के तहां मील के पत्थर की तरह यथावत बने रहे। इसलिए हमारे राजनेता अपने मन के मुताबिक इनकी तरह तरह की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं, जिससे राष्ट्र हित प्रभावित होता है। पांचवां, फिलवक्त भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा में कांगेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद और पर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो कुछ भी कहा, वह यदि सही नहीं है तो ज्यादा गलत भी नहीं है लिहाजा, इस मुद्दे पर आधुनिक सोच विकसित करनी चाहिए। साथ ही कतिपय संवैधानिक/कानूनी कमियों को दूर किया जाना चाहिए, ताकि कभी भारतीय समाज को माला की तरह जोडने वाली जाति प्रथा आरक्षण उत्प्रेरित

सामाजिक दट की वजह न बन जाये। जैसा कि महसूस किया जा रहा है इसलिए आरक्षण के आधार को जाति-धर्म-भाषा नहीं बल्कि आर्थिक आधार का किया जाना चाहिए इसे रोटेशनल बनाकर सबको लाभान्वित किया जाना वाहिए, जो न्यायिक तर्क वितर्क के मद्देनजर नहीं लगता है। छठा, उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई 2024 मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, जिन्हें अपनी जाति के बारे में भी नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात करते हैं । यह बात एक हद तक सही भी प्रतीत हो रही है ! इसलिए ऐसे लोगों की जाति व धर्म के लिए भारत में स्पष्ट कानूनी प्रावधान तय किए जाने की जरूरत है, जो तक और तथ्य की कसौटी पर खरा हो। व्योंकि वैदिक जाति या धर्म की अवधारणा पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जिसरकी उपेक्षा संवैधानिक भारत में होना आम बात बन चुकी है। सातवां, राहुल गांधी पर सदन में हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने इसके पहले ये भी कहा था कि असत्य के पैर नहीं होते हैं, जिसके चलते ये कांग्रेस के कधे पर सवारी करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर सवारी करता है, वैसे ही राहल गांधी के कंधे पर असत्य का बंडल होता है। तभी तो अनुराग ठाकुर की इन टिप्पणियोंमें हगामा बढ़ गया । इसलिए सीधा सवाल है कि अनुराग टाकर के इस ब्यान के बाद सदन में जो जमकर हंगामा शुरू हो गया और काग्रेस के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, वह कितना जायज है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता है। यदि जनप्रतिनिधिगण हंगामा करने के बजाय तत्सम्बन्धी कानून बनाने की मांग करें तो ऐसे विरोधाभासों को टाला जा सकता है।

आठवां, संयुक्त विपक्ष हंगामा करने के बजाय उन लोगों की एक अलग जातीय कोटि व धार्मिक कोटि बनाने की मांग करे, जिनके माता-पिता भिन्न-भिन्न जातियों या सम्प्रदायों से है, क्योंकि उनकी संतान वर्णसंकर हुई। चूंकि भारतीय समाज पितृसतात्मक समाज है, इसलिए यहा पिता की जाति या धर्म को स्वीकार करने की परम्परा प्रचलित है, जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इससे सम्बन्धित जाति/ धर्म का मूलगुण दुषित/ भ्रमित होता है। इसी तरह से साधुओं की भी एक अलग जाति बनाने की जरूरत है।

नौवां, आप मानें या न माने, किन्तु वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों के लिए ही वर्णसंकरता की परिकल्पना मौजूद है, जिसकी चतुराई

और उसके सभावित दुष्परिणामो के बारे में वैदिक साहित्य द्वारा पहले ही आगाह किया जा चुका है। हालांकि, तथाकथित प्रगतिशील वामपंथी लोगों के पास स्वस्थ सामाजिक - सांस्कृतिक चिंतन का अभाव होने के चले न तो वर्ण संकर लोगों की अलम जाति तय हुई और न ही अंतरधार्मिक शादी- विवाह करने वालों के लिए अलग धर्म तय किया गया । जबकि भारतीय समाज में इन्हें कहीं दोगलवा तो कहीं दगामिया कहे जाने की परंपरा प्रचलित है, जिसे अबतक कानूनी वर्गीकरण हासिल नहीं है।

इसलिए उम्मीद है कि इस बहस के बाद इनका भी कानूनी वर्गीकरण किया जाना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों को जातीय आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए या फिर किस कोटि से दिया जाए, उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए । दसवां, संच तो यह है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जातीय जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर जो संग्राम मचा हुआ है, वह आगामी विधानसभा चुनावों व यूपी उपचुनाव के दृष्टिगत विपक्ष की एक सुनियोजित सियासी रणनीति है। इन सबके पीछे विपक्षियों की मौके पर चौका लगाने वाली रणनीति काम कर रही है, जिसके चलते 10 साल बाद ही सही पर वह संसद में मजबूत होकर लौटा है। तभी तो संयुक्त विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर सदन में जमकर बवाल काटा। लोक-सभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुख कर दी।

सावन तो आता है पर झूले नहीं लाता

आज से नहीं, बल्कि सदियों से सावन महीने का झूलों से गहरा नाता रहा है। सनातनी परंपरा के लिहाज से सावन को झूला झूलने वाला माह कहा गया है। हालांकि, झूला झूलना सिर्फ सनातन परंपरा तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक धर्म के लोग इस पर्व में सहस्र शामिल होते रहे हैं। समय बदला, तीज-त्यौहार और रिवायतें भी बदल गईं। साथ ही झूलों की परंपराएं भी। अब कहीं भी सावन के झूले नहीं दिखाई पड़ते। गांवों में दिख जाएं, तो बड़ी बात है। पर, याद सभी करते हैं कि सावन तो आता है लेकिन अपने साथ झूले नहीं लाता। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे झूले कहीं बीच में छूट गए हैं। इस परंपरा के विलुप्त होने के कुछ वास्तविक कारण भी हैं। घरों में आंगनों का खत्म होना, बाग-बगीचे, तालाब-पोखर नष्ट हो गए हैं। पैड़-पौधों को लगाने में लोग कंजूसी दिखाते हैं। तेजी से बढ़ती आबादी के चलते आवासीय जगह सिमट गईं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, एकाध दशक पूर्व से झूले की परंपराएं धराशायी हुई हैं। सन् 1999 के बाद जैसे ही 2000 में जमाने ने प्रवेश किया, झूले शून्यता की ओर बढ़े। दरअसल, ये ऐसा वक्त था, जहां से जमाने ने खुद को मॉर्डर्न होना आरंभ किया। तभी से पुरानी परंपराओं ने तेजी से तौबा कहना शुरू किया। फ्लैट संस्कृति का बढ़ना, कच्चे घरों की जगह पक्के मकानों का निर्माण, आमजनों की पहुंच तक फोन-मोबाइल की रीच, नई पीढ़ी का पुरानी रिवायतों से मुंह मोड़ना, जैसे कई कारण हैं। स्थिति आज ये है, झूलों का रिवाज अब इतिहास बन गया है नई पीढ़ी के लिए। मौजूदा समय की आधुनिक चकाचौंध में बुजुर्ग गुजरे जमाने को याद करके अपने मन को मसोसते हैं। बदलते वक्त को वह रोक भी नहीं सकते। उन्हें याद आते हैं उनके देखे हुए पुराने दिन, सावन में भीनी-भीनी बारिश का होना और कजरी-गाने गाकर झूला झूलती महिलाएं, हिंदी फिल्मों के बजते गाने, किसी का भी मन मोह लेते थे। ऐसा लगता है कि मानो जैसे आधुनिक मोह-माया ने हम सभी को पिंजरों में कैद कर लिया हो। हालांकि शहरों के मुबाकले ग्रामीण अंचलों में सावन माह का महत्व अब भी थोड़ा बहुत बचा है। पर ज्यादा नहीं, धीरे-धीरे गांवों में भी महानगरों जैसे हालात होते जा रहे हैं। सावन को वेद-पुराणों में पवित्र तो कहा ही गया है साथ ही दो और खास बातें जुड़ी हैं। अव्वल, बारिश और दूसरा झूला। बारिश के दीदार तो होते रहते हैं। पर, झूले कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं देते। अन्य वस्तुओं की भांति झूलों का जमाना रिमिक्स होकर लौटेगा, ऐसा भी नहीं लगता।

गांव की सखियों का झुंड झूलों के बहाने बाग-बगीचों में मिलता था। सखी शादी होकर ससुराल भी चली जाती थी, तब झूले मिलाप का जरिया बनते थे। यही कारण था महिलाएं सावन के आने का बेसब्री से इंतजार करती थीं। बदलते युग के साथ उन्होंने इंतजार करना भी छोड़ दिया।

आधुनिक युग ने बहुत कुछ बदल दिया। देशी किस्म की अनगिनत परम्पराएं व रीति-रिवाज विलुप्त कर दिए हैं। इस कड़ी में सावन माह में झूला झूलना भी शामिल है। एक जमाना था, जब झूलों का ग्रामीण औरतें बेसब्री से इंतजार करती थीं कि कब सावन माह का आगमन हो और वो पेड़ों पर रस्से बांधकर झूला झूलें। पर, अफसोस सावन तो हर साल आता है लेकिन झूले नहीं।

झूले के लिए राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान जैसे राज्य विख्यात थे। उनके लिए बिना झूलों के सावन अधूरा होता था। युवा लड़कियां के अलावा घरों की बूढ़ी औरतें भी सावन की फुहारों में सराबोर होती थीं। एक-डेढ़ दशक पहले जन्में युवाओं को तो नहीं पता होगा। पर, बीस-बाईस वर्ष का नौजवान जरूर झूले का इतिहास याद करता होगा कि सावन के महीने में गांव की युवतियां पेड़ों पर कैसे झूला झूलती थीं।

झूले के लिए राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान जैसे राज्य विख्यात थे। उनके लिए बिना झूलों के सावन अधूरा होता था। युवा लड़कियां के अलावा घरों की बूढ़ी औरतें भी सावन की फुहारों में सराबोर होती थीं। एक-डेढ़ दशक पहले जन्में युवाओं को तो नहीं पता होगा। पर, बीस-बाईस वर्ष का नौजवान जरूर झूले का इतिहास याद करता होगा कि सावन के महीने में गांव की युवतियां पेड़ों पर कैसे झूला झूलती थीं।

एक मनमोहक नजारा होता था, जब झूला झूलते औरतें आपस में गीत गातीं थीं। हंसी-मजाक, ठिठोलियां करती थीं। उन लम्हों से आज के युवा तकरीबन अनभिज्ञ हैं। वो झूला और सावन पर्व के संबंध को बिल्कुल नहीं जानते। कम उम्र की लड़कियां और ब्याह शादी वाली औरतें स्थानीय लोकगीत व कजरी गाती थीं जिन्हें सुनने के लिए पुरुषों का आसपास जमावड़ा लगता था। बुजुर्ग औरतों की कजरी गवाई सुनने लायक होती थी। क्योंकि कजरी देहाती व खाटी देशी किस्म की वह विधा है जिसमें सावन, भादों के प्यार-स्नेह, वियोग, व मधुरता का मिश्रण होता था। धीमी-धीमी बारिश में कजरी गाने का मजा कुछ और ही होता था। सावन का सौंदर्य और परंपरागत कजरी की सुगंधित मिठास वर्षा बहार का जो वर्णनलोक गायन की विधा कजरी में है, वह किसी और में नहीं। लेकिन अब न झूले रहे, न कजरी को गाने वाली औरतें। दोनों परंपराओं ने एक साथ मिलकर दम तोड़ दिया। नए जमाने की कामकाजी औरतें कजरी के संबंध में कुछ भी नहीं जानती।

सावन और झूलों की परंपरा का दीदार थोड़ा-थोड़ा कोरोना काल में हुआ था। जब, ऐसा महसूस हुआ कि समय खुद भागते-भागते थक गया। इसलिए कोरोना का बहाना लेकर थोड़ा ठहरा था। कोरोना महामारी के चलते लोग शहर छोड़कर गांवों में पहुंचे थे, तो उन्हें कई जगहों पर झूले लगे दिखे, उन्हें देखकर महसूस किया, कि गुजरा जमाना फिर लौट आया। औरतों ने बागों में झूले सजाए, डीजे लगवाए। बीते समय की भांति झूला झूले, गाने गाए, उनको देखकर लोगों ने खूब आनंद उठाया। बच्चों के लिए वो दृश्य एकदम नए थे।

दरअसल झूले कैसे होते हैं, किस तरह झूले जाते हैं ये सब उन्होंने किताबों में ही पढ़ा है। खैर, गनीमत समझें कि कोरोना ने पुरानी परंपराओं के दीदार तो करवाए।

पर, जिंदगी एक बार फिर से भागम-भाग में फंस गई है। झूलों के कम अवधि वाले दृश्य हम सबके लिए बेमानी हो गए हैं।

पशुधन सेवा, ईश्वर सेवा: डॉ. जी.के. सिंह

गोरखपुर (जकेबी)। मुख्य अतिथि अपर निदेशक पशुपालन डॉ. जी. के. सिंह ने पशु चिकित्सालय सदर पर सेवानिवृत पशुधन कर्मी हरिश्चन्द्र यादव के विदाई / सम्मान समारोह में कहा मूक पशुओं कि सेवा सच्ची ईश्वर सेवा है।

डॉ. सिंह ने यादव के कार्य एवं सद्व्यवहार की सराहना की।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी - डॉ. धर्मेंद्र पांडेय, डॉ. बी. के. सिंह, डॉ.नवीन कुमार वर्मा, डॉ. राहुल सिंह, डॉ. सुधीर पटेल, डॉ. मनीष गुप्ता, गजेंद्र मिश्रा, विनय सिंह, सुरेंद्र यादव, अखिलेश पांडेय, राजेश कुमार, दुर्गेश सिंह, फरहान खान, स्वतंत्र सिंह, मनोहर लाल, दिनेश कन्नौजिया एवं गो सेवक वरुण वर्मा बैरागी आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सदर डा. एसके वर्मा तथा संचालन गोसेवक वरुण वैरागी ने किया।

मानवता की मिसाल: झोले में मिला नवजात शिशु, वर्दी ने बचाई

देवरिया(सांध्य हिन्दी दैनिक)। चाय की दुकान के सामने झोले से शिशु के रोने की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दी। लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए कोतवाली के कोबरा के कांस्टेबल कृष्ण गोपाल और दीपक कुमार पहुंचे। यूपी के देवरिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बंद एक चाय की दुकान पर शनिवार की सुबह लगभग पांच बजे झोले में टंगा एक नवजात मिला। नवजात के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे कांस्टेबल ने नवजात को झोले से निकालकर मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वॉर्ड में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर है। शहर के ट्यूबवेल कॉलोनी के एक चाय की दुकान के सामने झोले से शिशु के रोने की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दी। लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी।

सूचना पर तत्परता दिखाते हुए कोतवाली के कोबरा के कांस्टेबल कृष्ण गोपाल और दीपक कुमार पहुंचे। उन्होंने नवजात को झोले से सुरक्षित निकाला और मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में भर्ती कराया। जहां नवजात की हालत स्थिर है। झोले में काफी देर रहने के कारण डाक्टरों ने अभी निगरानी में रखा है। वहीं नवजात को किसने झोले में रखकर छोड़ा है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

सदर कोतवाल दिलीप सिंह ने बताया कि स्थानीय कॉलोनीवासियों की सूचना पर पुलिस गई थी। नवजात को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नवजात खतरे से बाहर है।

आश्रय गृह में हुई 14 मौतों पर दिल्ली सरकार पर स्वाति मालीवाल ने साधा निशाना

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा आशा किरण आश्रय गृह में हाल ही में हुई मौतों के संबंध में कार्रवाई की कथित कमी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कथित तौर पर कैदियों की मौत स्वास्थ्य समस्याओं और कुपोषण के कारण हुई। मालीवाल ने कहा कि पिछले 20 दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में 13 मौतें हुई हैं। कारण अभी तक ज्ञात नहीं हैं। जब मैं डीसीडब्ल्यू में थी, तो मैंने यहां की स्थिति का निरीक्षण किया था। यहां स्थिति बहुत खराब है क्योंकि यहां न तो उचित स्टाफ है और न ही उचित डॉक्टर हैं।

मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पहले एक रिपोर्ट दायर की थी जो दिल्ली सरकार को सौंपी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने और एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि हमने उस समय एक रिपोर्ट बनाई और इसे दिल्ली सरकार को सौंप दिया, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगी। दिल्ली सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में हाल ही में हुई मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को 48 घंटे के भीतर मामले की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई की दूसरी छमाही में 10 महिलाओं सहित 12 रोगियों की मृत्यु हो गई, जिसमें 45 से अधिक कैदी थे, जो असामान्य रूप से बड़ी संख्या में बाहरी उपचार के लिए भेजे गए थे। हालाँकि, 12 में से केवल एक शव ही शव परीक्षण के लिए प्राप्त हुआ था। सभी मृतक रोगियों में दस्त और उल्टी के समान लक्षण प्रदर्शित हुए और कैदियों के शवों को आमतौर पर डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल भेजा गया, जो सुविधा से 2 किमी दूर है, जहां उन्होंने बीमार कैदियों का इलाज

घूँघट की बगावत
04 अगस्त 2024
प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

मुख्यमंत्री ने किया 55.43 करोड़ लागत की 14 कार्ययोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास

गोरखपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कुल 55.43 करोड़ लागत की 14 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण/शुभारंभ/ शिलान्यास के साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मेडिकल एवं पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट का वितरण भी किया। मुख्यमत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया उसमे 6.12 करोड़ की लागत से स्थापित बर्न यूनिट, 2.68 करोड़ की लागत से स्थापित नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट लैब, 8.5 करोड़ की लागत से फार्मेसी कॉलेज के विस्तारीकरण निर्माण कार्य तथा 98 लाख की लागत से नवनिर्मित स्टेडियम की चहारदीवारी का लोकार्पण, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं हेतु 30.31 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले मैरिड छात्रावास का शिलान्यास तथा मेडिकल कॉलेज में स्थापित सीटी स्कैन मशीन, जेनेटिक मेडिसिन व पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक विभाग की ओपीडी, मिल्क बैंक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैंपल कलेक्शन सेंटर, लिथोट्रिप्सी मशीन आदि शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज सभी को इन योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो बीआरडी मेडिकल कालेज को एक उच्च स्वास्थ्य चिकित्सा के रूप में विकसित करने में मददगार साबित होगा। इस मेडिकल कालेज के माध्यम से पूर्वी उ0प्र0 की 5 करोड़ जनता के लिये उनकी स्वास्थ्य आकांक्षाओं के अनुरूप बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा को विकसित किया जा रहा है। इस योगदान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा विभाग के साथ सभी आम जनमानस बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि सभी ने पिछले 30 से 35 वर्षो में बीआरडी मेडिकल कालेज में पतन और उत्थान की कहानी को बहुत निकट से देखा है। यहां 1996-97 में मेडिकल छात्रो ने इसके बंद होने से रोकने के लिए सहायता तक मांगी थी। किन्तु आज वह छात्र देश के अलग अलग भागों में अच्छे डाक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रहे है। उन्होंने कहा कि जब वे गोरखपुर के सांसद थे तो इस कालेज के उत्थान के लिए उन्होंने लगातार आवाज उठायी थी। एक समय यहां संसाधनों का अभाव था, छात्रो की डिग्री खतरे में थी। इस मौसम में तो यह मेडिकल कालेज पूर्वी उ0प्र0 के लोगों के लिए अभिशाप बन जाता था। इंसेफ्लाइटिस से मौते होती थी। अब शासन के संकल्पित प्रयासो से आज यहां सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इंसेफ्लाइटिस वार्ड एकदम स्वच्छ एवं साफ है। मरीज और मरीजों के परिजनों के चेहरे पर आज खुशी दिखाई पड़ती है। उ0प्र0 शासन के दृढ संकल्प होकर कार्यो के करने के परिणाम स्वरूप पिछले 6 वर्षो में इसकी तस्वीर बदल गयी है जिसे सबने देखा है। इस वर्ष इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त केवल 40 मरीज आये। कोई भी मौत अब नही हुयी है। ये सारी चीजे दशार्ती है कि कैसे इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। यह एक माडल एवं स्टडी है जिसे दुनिया के सामने रखा जा सकता है कि डाक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभागों समन्वय के माध्यम से एक रणनीति बनाकर इस बीमारी पर सफलता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के आभारी है जिन्होंने गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम के लिए कदम बढाया। उन्होंने इस मेडिकल कालेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लाक का निर्माण करवाया। कोरोना काल खण्ड में इस ब्लाक ने सैकड़ो लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गोरखपुर में आईसीएमआर की रीजनल वायरोलाजी सेंटर स्थापित कराया है। एनआईपी पूणे के बाद बीआरडी मेडिकल कालेज इकलौता ऐसा संस्थान जहां इस तरह का संस्थान कार्य कर रहा है। उन्होंने आहवान किया कि सभी को वहां जाकर इसकी कार्य प्रणाली का अवलोकन

करना चाहिए। उन्होने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आभारी है जिन्होंने पूर्वी उ.प. व गोरखपुर के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु एम्स जैसा संस्थान दिया है। बीआरडी मेडिकल कालेज बहुत पुराना संस्थान है। निरीक्षण के दौरान यह पाया कि यहां देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर आदि जगहों के लोग यहां ईलाज के लिए आए है, जबकि इन जिलो में मेडिकल कालेज शुरू हो चुके है। यह उनका बीआरडी मेडिकल कालेज के प्रति विश्वसनीयता को दिखाता है। एम्स बड़ा संस्थान होने के बावजूद वे बीआरडी मेडिकल आए है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यही समय है जब बीआरडी मेडिकल कालेज के सभी छात्र व फैकल्टी मेम्बर मिलकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बीआरडी मेडिकल कालेज को एक नयी ऊंचाई पर ले जाने और प्रयास करे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाए है, जिन्हें डिजिटल प्लेटफार्म पर देखा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध करा रही है। आज सभी मेडिकल कालेज देश एवं दुनिया के अच्छे चिकित्सा संस्थान से एमओयू कर सकते है। डिजिटल व्यवस्था को आगे बढ़ा सके एवं आनलाईन प्लेटफार्म पर सुविधा प्राप्त हो सके इसके लिए अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन/टैबलेट से भी आच्छादित किया जा रहा है। प्रदेश का युवा तकनीकी दृष्टि से स्वयं को अक्षम न समझे यह अत्यंत जरूरी है। सरकार इसके लिए युवाओं के साथ खड़ी है। उनकी आकांक्षाओं को उडान देने के लिए सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक डाक्टर में आम जनमानस बहुत ही श्रद्धा का भाव रखता है। श्रद्धा एवं समान के भाव को सभी डाक्टरों को संजोए रखने की आवश्यकता है। उसके लिए सभी डाक्टर्स को अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति का पारिवारीजन जब बीमार होता है तो वह बहुत ही तनाव में रहता है। इसके लिए भी डाक्टर्स को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने भी इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाया है। आयुष्मान कार्ड के तहत प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख लोगों को 5 लाख प्रतिवर्ष मुफ्त ईलाज से आच्छादित किए गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख 88 हजार लोगों को ईलाज हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हेतु आज प्रदेश में धन की कमी नही है। 108 एम्बुलेंस सेवा किसी भी जिले से मरीज को अस्पताल पहुंचाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब मरीज साथ आये अटेडेंन्ट के साथ दुव्यवहार किया जाता है तो लोगों में मेडिकल तथा पैरामेडिकल टीम के प्रति गलत संदेश जाता है। सभी मेडिकल स्टाफ को धैर्य से काम करना चाहिए। धैर्य उनकी पहचान होनी चाहिए। चिकित्सक की मरीज के प्रति सद्भावना एवं मीठे बोल उसके जीवन को संबल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में प्रत्येक सीएचसी, पीएचसी एवं जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बृहद स्तर पर विस्तार किया गया है। शासन द्वारा स्पेसलिस्ट चिकित्सक की नियुक्ति के लिए जिले की कमेटी को स्वतंत्रता दी गयी है। कोई भी डाक्टर इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिस उ0प्र0 में बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मण्डल में एक भी मेडिकल कालेज नही था, आज इसी पूर्वी उ0प्र0 में बस्ती, गोण्डा, अम्बेडकर नगर, बहराइच, देवरियां, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, अमेठी जिलों में मेडिकल कालेज संचालित हो चुके है। बलरामपुर में मेडिकल कालेज का निर्माण हो रहा है। रायबरेली में एम्स जैसा संस्थान है, बलिया में पीपीपी मोड में मेडिकल कालेज का संचालन शुरू हो चुका है जहां इस वर्ष एम0बी0बी0एस0 प्रथम वर्ष में प्रवेश का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि आज लगभग प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कालेज की उपस्थिति को सुनिश्चित कर उ0प्र0 वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज की दिशा में आगे बढ़ चुका है। उ0प्र0 में इस वर्ष 10500 एम0बी0बी0एस0 की सीटो पर प्रवेश होगा। सरकार चिकित्सक की कमी को पूरा करने के दिशा में आगे बढ़ चुकी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इसके लिए शासन द्वारा कार्यो को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नये मेडिकल कालेज के निर्माण के साथ पुराने मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बीआरडी मेडिकल कालेज में सिटी स्कैन मशीन का शुभारम्भ नेशनल लाइफ सपोर्ट लैब की स्थापना का शुभारम्भ, लिथोट्रिप्सी मशीन का शुभारम्भ, फामेर्सी कालेज के विस्तार निर्माण कार्य का लोकार्पण, जेनेट्रिक मेडिसिन विभाग की ओपीडी का शुभारम्भ, माइक्रोबायोलाजी विभाग में सैम्पल कलेक्शन सेंटर का शुभारम्भ आदि कई कार्य किये गये है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी प्रयास को उसका परिणाम ही मूल्यांकन करता है। शासन के प्रयास को शासन नही बल्कि नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट मूल्यांकित करती है। उ0प्र0 में 2011-14 में मातृत्व मृत्यु दर 285 थी आज वह घटकर 150 से 165 के बीच आ गयी है। शिशु मृत्यु दर में भी कमी आयी है, जो पहले 57 शिशु प्रति हजार थी, आज वह 30 से 35 शिशु प्रति हजार है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम बताते है कि हमार प्रयास अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में और भी प्रयास करना है। नई तकनीक एवं नये शोध के अनुरूप लगातार आगे बढना है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत भी इस दिशा में अनेक प्रयास हो रहे है।

इस अवसर पर विधायक पिपराइच महेन्द्रपाल सिंह तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने भी लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डा0संजय निषाद, महापौर डॉ0 मगलेश श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य डॉ0 धर्मेंद्र सिंह, विधायकगण श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, डॉ0 विमलेश पासवान, इं0 सरवन निषाद, प्रदीप शुक्ला, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, तथा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।

आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न

गोरखपुर। मण्डलायुक्त/अध्यक्ष गीडा, अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। उन्होंने बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सहायक के रूप में किसी निजी व्यक्तियों को काम पर न रखे, कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जांच में पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

समीक्षा के दौरान अध्यक्ष/मण्डलायुक्त ने भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लैण्ड बैंक बढ़ायें जाने के दृष्टिगत कार्य प्रगति को बढ़ाते हुए मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाय तथा लक्ष्य प्राप्ति हरसम्भव प्रयास कर सुनिश्चित किया जाय। वित्त अनुभाग से सम्बन्धित प्रस्तावित प्राप्ति/व्यय की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने पुराने/बड़े बकायदारों की सूची बनाकर पूरी आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने गीडा में प्राप्त होने वाले मानचित्रों की समीक्षा करते हुये, जो मानचित्र सही दाखिल किये गये हैं उन्हें समय से स्वीकृत करने और मानचित्रों को ऑनलाइन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर बताया गया कि इस दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है सितंबर माह के अंत तक सभी मानचित्रो को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मण्डलायुक्त द्वारा अभियंत्रण अनुभाग (सिविल)/विद्युत विभाग/यांत्रिक अनुभाग/सम्पत्ति अनुभाग/विधि अनुभाग आदि के प्रगति कार्यों की समीक्षा करते सभी कार्यों को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

लापरवाह शिक्षकों पर कार्यवाही का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

गोरखपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने 165 प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षकों की उपस्थिति, मध्यान भोजन किताबों के वितरण आदि की स्थिति की जांच उप जिलाधिकारी गण, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार की टीम बनाकर औचक जांच करायी।

जांच के दौरान लगभग 45 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित पाये गये शिक्षको का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करने का निर्देश देते हुये कहा है कि इस प्रकार की जांच आगे भी जारी रहेगा और लापरवाह शिक्षको पर कार्यवाही किया जायेगा।

उन्होने कहा कि आग्रिम जांच मे भी पुन शिक्षक अनुपस्थित पाये जाते है तो विद्यिक कार्यवाही किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मेडिकल एवं पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट का वितरण भी किया।

मंडलायुक्त ने किया सैनिक स्कूल का स्थलीय निरीक्षण

गोरखपुर। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने खाद कारखाना परिसर में 50 एकड़ में निमार्णाधीन सैनिक स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया।

मण्डलायुक्त ने आडिटोरियम, मल्टीपरपज हॉल, स्विमिंग पूल, एक्टिविटी रूम, शूटिंग रेंज, हेल्थ सेंटर, स्टोर समेत अन्य निर्माणधीन कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त को कार्यदायी संस्था ने बताया कि सभी कार्य लगभग पूर्ण हो चुकें हैं फिनिशिंग आदि का कार्य चल रहा जो अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा जिसपर मंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्था को फिनिशिंग व अन्य कार्यों को यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण करने, साथ ही सभी ब्लाकों को जोड़ने वाली सड़कों की सही ढंग से फिनिशिंग करने को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझौता करने पर संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल में कक्षा 6

से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी यहां पर छात्र छात्राओं को अलग-अलग हॉस्टलों की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

प्री प्राइमरी पढ़ाई बदहाल बच्चों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना

महराजगंज (जीकेबी)। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सरकार भले ही गंभीर है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत खराब है। कई केंद्रों में शौचालय, पानी से लेकर बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। वह प्राथमिक स्कूल के भवन में संचालित हो रहे हैं, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अभिभावक भी केंद्रों पर बच्चों को भेजने से कतराते हैं। बच्चों का मन बहलाने के लिए दो वर्ष पहले खिलौने मिले थे जो अब टूट चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं के नाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं। इनमें से अधिकांश पर मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं जो खिलौने बच्चों का मन बहलाने के लिए दिए गए वह टूट गए हैं। प्री प्राइमरी पिपरदेउरा की पड़ताल की गई तो प्राथमिक स्कूल के भवन में संचालित मिला। परिसर में पानी भरने के कारण बंद था। वहीं चिउरहां में भवन जलभराव के कारण बंद रहा। गबडुआ में फरीदा बानों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका निशा देवी मौजूद मिलीं। नामांकित 32 बच्चों में 11 मौजूद मिले। ऊषा देवी ने बताया कि दो वर्ष पहले बच्चों के लिए मिले खिलौने टूट चुके हैं।

जलभराव के कारण कुछ स्कूलों में दिक्कत है वहां कक्षा का संचालन नहीं हो पा रहा है। जहां आज केंद्र बंद मिले हैं, वहां के आंगनबाड़ी से जवाब मांगा जाएगा। समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

-दुर्गेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी

धर्मांतरण विरोधी कानून स्वागत योग्य: मिलिंद परांडे

गोरखपुर (जीकेबी)। में विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे का प्रवास था, इस दौरान कार्यकताओं के साथ विभिन्न बैठकों के माध्यम से संवाद हुआ।

विशिष्ट वर्ग की बैठक का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल , प्रांत मंत्री नागेंद्र ने संयुक्त रूप से भगवान श्री राम दरबार के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे का प्रवास था, इस दौरान कार्यकताओं के साथ विभिन्न बैठकों के माध्यम से संवाद हुआ।विशिष्ट वर्ग की बैठक का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे, विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल , प्रांत मंत्री नागेंद्र ने संयुक्त रूप से भगवान श्री राम दरबार के सम्मुख दीप प्रज्वलंकर किया।

धर्मांतरण विरोधी कानूनी स्वागत योग्य कदम

विभिन्न बैठकों में युवाओं, व्यवसायी एवं विशिष्ट वर्ग कार्यकताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध 2019 में बनाए गए कानून को और कठोर बनाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। कानून बनने के बाद भी लव जिहाद व अवैध धर्मान्तरण की घटनाएं, सख्त शासन के बाबजूद रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 के विधानसभा में पारित होते ही अब आशा की जा सकती है कि जो संगठित अपराधी हैं न सिर्फ वे, अपितु, शेष जिहादी व मिशनरी भी अपने कुकृत्यों से डरेंगे।

दंड के कठोर प्रावधान ही रोकेंगे धर्मांतरण

मिलिंद ने कहा कि विधेयक में शिकायत कताओं का दायरा, आजीवन कारावास की सजा, दंड की राशि को बढ़ाया जाना तथा अवयस्क और दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षार्थ विशेष व्यवस्था सराहनीय हैं। ऐसे कठोर प्रावधान, निसंदेह, उन अपराधी वृत्ति के लोगों के मन में

डर पैदा करके भगवान श्री राम, योगेश्वर श्रीकृष्ण व भोले बाबा की इस पुण्य धरा को धर्मांतरण द्वारा राष्ट्रांतरण के दिवास्वप्न देखने वालों के चंगुल से मुक्ति दिलाने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। यूपी सरकार ने ना सिर्फ 2019 में यह कानून बनाया अपितु गत 5 वर्षों में उसका कठोरता से पालन भी सुनिश्चित करवाया। इस दौरान श्री परांडे ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव तक भी भारत के मात्र 10-11 राज्य ही धर्मांतरण विरोधी कानून ला पाए। उनमें भी इतनी कठोर सजा का प्रावधान, संभवतया उत्तर प्रदेश के इस कानून में ही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शेष राज्य सरकारें भी इस बारे में त्वरित पहल कर, अपने अपने राज्यों को अवैध धर्मान्तरण के अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे। जिन राज्यों में अभी इस बारे में कोई कानून नहीं है, उनको भी शीघ्र, अतिशीघ्र एक कठोर दंड विधान के साथ यह पारित करने चाहिए और जिन कानूनो की स्थिति लचर है, वहां उन्हें और कठोर बनाए जाने के साथ उनका पूर्ण मनोयोग से पालन किया जाना भी बहुत जरूरी है।

धर्मांतरण विरोधी कानून अन्य राज्यों में भी लागू हो

विश्व हिंदू परिषद आशा करती है कि इस कानून का अन्य राज्य सरकारें भी अनुसरण करेगी जिससे जो लोग लालच, प्रपंच, धोखे या बलपूर्वक धर्मांतरण, लव जिहाद और नारी शक्ति के चीर हरण कर टुकड़े टुकड़े करने में जुटे हैं वे अपनी इन नापाक हरकतों से बाज आ सकें, साथ ही समाज को भी इन मामलों में सजग रहकर समय पर उचित कार्यवाही के लिए शासन प्रशासन का सहयोगी बन, अपराधियों को कठोर सजा दिलाए जाने के लिए आगे आना होगा।

नौ हजार से अधिक कार्यक्रम करेगा विहिप

उन्होंने पूरे देश भर में अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हिंदू जैन बुद्ध सिख शरणार्थियों के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि का अधिनियम के अंतर्गत भाप ने ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया में सक्रिय और पूर्ण मत से उनका सहयोग करेगा।उन्होंने आगे बताया कि 24 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद अपने षष्ठी पूर्ति वर्ष के समापन के निमित्त 9000 से अधिक कार्यक्रम देश भर में प्रखंड स्तर में विसाल रूप से करेगा। आज हिंदू समाज के लिए पिछले डेढ़ हजार साल का सबसे अनुकूल कालखंड भारत वर्ष में आया है। इस समय भारत के उत्थान के लिए हिंदू युवाओं में को आगे बढ़ कर बड़ी भूमिका निभानी चाहिए उनको स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेकर अपनी स्किल को डेवलप करके देश को समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। नौजवानों को ऐसे प्रशिक्षण करा कर व्यवसाय दिलाने में सहयोग किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांत के उपाध्यक्ष डॉ आरपी शुक्ला, प्रांत संगठन मंत्री राजेश, संगठन मंत्री दीपेश, प्रांत मंत्री नागेंद्र, क्षेत्र के धर्म प्रसार प्रमुख प्रदीप पांडेय, संयोजक पूर्णेंदु, प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख डॉ डीके सिंह, प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख भागवत यादव, विभाग मंत्री शीतल मिश्रा, महानगर संगठन मंत्री सोमेश, संयोजक विनोद मिश्र, हिमांशु त्रिपाठी मंत्री अनूप शुक्ला, अभय प्रताप शाही, विश्वजीत शाही, विशाल जायसवाल सहित सैकड़ों विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

घूँघट की बगावत

04 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

4

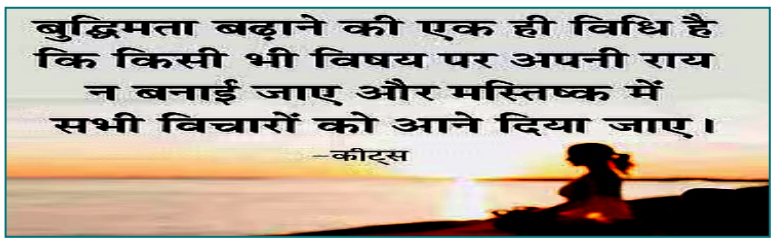

जातिगत जनगणना के दावों का सफल पदार्फास

अनुराग ठाकुर नें पीडीए विशेषज्ञ नेताओं को जाति के जाल में ऐसा उलझा दिया है कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। राहुल से एक्स पर लगातार पूछा जा रहा है कि वो अपनी जाति स्पष्ट करें। आजकल पीडीए के सभी पैंतरों पर पानी फिरता जा रहा है क्योंकि जनता जान गई है कि यूपी के लोकसभा चुनाव में पीडीए नें भाजपा के साथ छल किया और जो माहौल बनाया वह बिना धूर्तता के संभव नहीं था। अब जनता विपक्ष से ही सीधे हर मामले में सवाल जवाब करने लगी है, यह लोकतांत्रिक देश का शुभ लक्षण है और मोदी सरकार कि बहुत बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है । सोचिए जिस दिन जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी की बारी आएगी उस दिन भारत की अखंडता का क्या हश्र होगा ! जातिय उन्माद देश को गृहयुद्ध में झोक देगा जिसकी रणनीति अखिलेश और राहुल नें पहले से बना रखी थी लेकिन अनुराग ठाकुर के एक प्रश्न नें अखिलेश और राहुल के कुत्सित मानसिकता का पदार्फास कर दिया इसलिए अब जाति वाले प्रश्न पर दोनो पीडीए नेता तिलमिलाये नजर आ रहें।संसद में राहुल और अखिलेश की युवा जोड़ी अब मोदी के अनुभवी खिलाड़ियों अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे के ट्रैप में फँसते नजर आ रहें है। क्योंकि भाजपा नें पीडीए के दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसकी कराह अब राहुल और अखिलेश के भाषा से आ रही। भाजपा एवं संघ जातीय जनगणना के खिलाफ रही है क्युकि इससे असंतोष बढ़ेगा और अखंडता नष्ट होगी , जो कि सोशल जस्टिस के प्रमुख अंग हैं, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक जज नें भी जातिवादी आरक्षण को नकाराते हुए सुझाव दिया है की आरक्षण केवल दबे कुचलें दलित और पिछड़ो को मिले ना की अमीर और सम्पन्न दलितों और पिछडो की पीढ़ियों को। भाजपा अब भी दलितों पिछड़ो और आदिवासियों के साथ खड़ी है उसके इसी कमजोरी को विपक्ष भुनाना चाहता है। आज भाजपा पुनः बेहद मजबूत स्थिति में है, विपक्ष को कोई रास्ता नही सूझ रहा, हालांकि सवर्ण वोटरों की नाराजगी ने भाजपा के पिछड़ों पर अधिक फोकस करने की राजनीति को नकारते हुए यूपी में सबक सिखाकर उसे बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करने से रोक दिया पर सवर्ण पुनः भाजपा के साथ जुड़ जायेंगे तो पीडीए फिर हवा हवाई हो जाएगी। क्योंकि वह सामाजिक न्याय वाली जातियों में ध्रुवीकरण कराने मे विफल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का पतन शुरू हो गया है, या कोई रास्ता निकाल लेगी । जाति-गणना की मांग कर रहे अखिलेश जब राहुल के बचाव में कुदे तो वह भूल गए की कुछ दिन पहले वो मिडियाकर्मीयों से उनकी जाति पूछ रहें थे। अरे तुम मिश्रा हो ! तो मिश्रा जी... अखिलेश ये भूल गए की जब आसमान की तरफ थूकोगे तो थूक वापिस तुम्हारे ही मुँह पर गिरेगी और जाति जनगणना वाले मसले पर ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में इसे रखा गया तथा उन्होंने सदन में इस चक्रव्यूह को तोड़ने की बात भी कही। जिससे चुनाव काल से लेकर अब तक पिछड़ा वर्ग अखिलेश और राहुल गांधी के साथ डटकर खड़ा हुआ पर जब राहुल की जाति पूछ ली गई तो घुप सन्नाटा ! क्यूंकि जाति एक ऐसा मसला है जो यदि जनगणना के दौरान देश में पूछ लिया जाए तो बहुतों को रोहिंग्या, बहुतों को इटेलियन पारसी और बहुतों को फिलिस्तीनि समर्थक साबित कर देगी । उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव ने यह साबित भी कर दिखाया कि सवर्ण भाजपा की ताकत है और अगर वो हटे तो पीडीए का धोखा लोग खाने लगेंगे।

जातिगत राजनीति के काट के लिए भाजपा के एक युवा तुर्क केन्द्रीय मंत्री अनुराग नें जो दाव चला उससे राहुल और अखिलेश पस्त नजर आए और ना सिर्फ पस्त हुए बल्कि बौखला गए जिसका सबूत उनके समर्थको द्वारा अनुराग ठाकुर का जगह जगह पुतला फुकने से परिलक्षित हुआ। कार्यकताओं को आगे कर यह सवाल उठाया गया कि आखिरी राहुल जाति क्यों बताए ! जबकि राहुल बताएं वे किस जाति के हैं ? जिसे अमूमन सारा देश भली-भांति जानना चाह रहा है। इस पर पूरे लगभग दस साल भाजपा आईटी सेल लगा रहा है। गांधी सरनेम पर भी रिसर्च जैसा आलम रहा है । वे मातृ पक्ष के हिसाब से इटेलीयन पारसी समुदाय से आते हैं। वैसे आरक्षण के मलाईदार घर में सदियों से जमे कुछ खास वर्गों के आधिपत्य पर विराम लगना चाहिए । इसी तरह अब चुनाव में संघ और सवर्ण भी इनके गले की हड्डी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक आरक्षण के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। मजबूरी में नेता फिलहाल इसे ढो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा दलित नेत्री मायावती का जिस तरह से सफाया किया गया यह सामने है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग नें सपा का सफाया किया वह भी सामने है। कल्याण सिंह नें बाबरी तुड़वाकर जबरदस्त काम किया जिसे भुनाकर आज भाजपा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहीं। कांग्रेस से अच्छे नेताओं को दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया। राहुल गांधी ने तो लगातार सामाजिक भागीदारी के असंतुलन पर कहा है कि अगर भारत की शीर्ष 200 कंपनियों और उनके मालिकों को देखा जाए तो एक भी आदिवासी, दलित या ओबीसी नहीं मिलेगा तो राहुल जी को समझना चाहिए की आरक्षण की मलाई उच्च पदों पर बैठे दलित और ओबीसी खा रहें पहले उसे मुक्त कराइयेगा और यही स्थिति राजनीती, न्यायपालिका से लेकर नौकरियों तक सभी क्षेत्रों में देखी जाती है, जिसमें 50 प्रतिशत लोग वो है जो आरक्षण की मलाई चाटकर पहलें उच्च पदों पर बैठते है फिर अपने पुत्र पुत्रीयों को भी आराम से वहीं मुफ्त की रेवड़ी खिला रहें जबकि शेष 50% लाचार दलित ओबीसी रेस से बाहर रह जाते हैं। हालांकि राहुल साफ तौर पर कहते रहे हैं कि ₹मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बड़े भारतीय कारोबारियों की मदद नहीं की जानी चाहिए। उनकी भी मदद की जानी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप उन्हें 100 रुपये की मदद कर रहे हैं, तो 90 फीसदी आबादी की भी उसी 100 रुपये से मदद कीजिए। जब देश में कांग्रेस नें जातिवाद को बढ़ावा दिया था तो अब ज्ञान देने वाले राहुल गांधी पर आरोप लगना लाजमी है। राहुल ने कहा था-ह्मेरी दिलचस्पी जाति में नहीं है। मेरी दिलचस्पी 'न्याय' में है। मैं कह रहा हूं कि भारत में 90 प्रतिशत लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई कार्रवाई करेंगे। मैंने केवल इतना कहा है कि आइए पता लगाएं कि कितना अन्याय हो रहा है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।कुल मिलाकर जातिगत जनगणना की मांग नाजायज और घातक है इसके जरिए देश को तोड़ा जाना है और आर्थिक और सामाजिक भागीदारी में असंतुलन पैदा करना है।

पंकज कुमार मिश्रा,
जौनपुर यूपी

जलवायु परिवर्तनः एक गंभीर चुनौती

देश में कहीं जल की अधिकता और कहीं कमी से किस प्रकार किसान नुकसान झेल रहे हैं, इस बारे में सर्वे रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। यह सर्वे रिपोर्ट बताती है कि देश के उत्तरी राज्यों में धान के खेतों के अवसर एक सप्ताह से अधिक समय ताक जलमग्न रहने की वजह से नए रोपे गए पौधे नष्ट हो जाते हैं। खेती पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत होने की जरूरत है। अगर किसानों की आमदनी में और गिरावट आती है तो उनमें निराशा का भाव बढ़ेगा। यह निराशा कई समस्याओं को जन्म देगी। फसलों की पैदावार में कमी के कारण खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराना स्वाभाविक है, जिससे अन्न की कमी से समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

कृषि अनुसंधान संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करके किसानों को उचित परामर्श देने की महत्ती जिम्मेदारी उठानी होगी। जलवायु परिवर्तन का खेती पर प्रतिकूल प्रभाव एक गंभीर चुनौती है, जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। सतत और अनुकूल कृषि प्रथाओं को अपनाकर सुनियोजित तरीके से जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही भावी पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव है।

जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। जलवायु परिवर्तन का का व्यापक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहा है। हमारी खेती भी इससे प्रभावित हो रही है। खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण करोड़ों किसान प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में आई एक सर्वे की रिपोर्ट खेती पर जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का खुलासा करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में प्रतिकूल जलवायु घटनाओं के कारण भारत में 80 प्रतिशत सीमांत किसानों को फसलों में का नुकसान उठाना पड़ा है।

दुनियाभर के विशेषज्ञ एक अर्से से जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में चेताते आ रहे हैं, लेकिन इसे अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया गया है जलवायु परिवर्तन पर चर्चा तो होने लगी हैं मगर इससे निपटने के लिए कारगर उपायों पर गंभीरता से काम नहीं हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है। कभी अधिक वर्षा तो कभी सूखे की स्थिति बन जाती है, जिससे फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। हाल के दो-तीन सालों में उच्च तापमान से फसलों की वृद्धि प्रभावित हुई है। गेहूं जैसी कई फसले अत्यधिक तापमान को सहन नहीं कर पाई, जिससे उनकी पैदावार घटी है। उच्च तापमान और नमी की स्थिति ने कीटों और रोगों के प्रकोप को बढ़ाया है।

उत्तरी भारत की कपास पट्टी में पिछले कई सालों से गुलाबी झुंडी कपास की फसल को चट कर रही है। फसलों के जिन रोगों के बारे में कृषि विभाग को पता है, उनसे निपटना ही भारी पड़ रहा है। ऊपर से यह आशंका भी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ नए रोग भी फसलों पर हमला कर सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए किसानों के पास उचित तैयारी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के अनेक नुकसान खेती को प्रभावित कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति बन रही है, इससे भूजल का अधिक दोहन हो रहा है, जो जलस्तर में गिरावट की वजह बन रहा है जहां कहीं अत्यधिक वर्षा देखने हो रही है, वहां इस कारण मिट्टी का कटाव होने से उसकी उर्वरता कम हो रही है। सूखे की स्थिति में मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, जिससे फसलों की वृद्धि में रुकावट आती है। जलवायु परिवर्तन का नुकसान किस कदर प्रत्यक्ष नजर

कोचिंग सेंटर के कारनामों का काला चिट्ठा देश के सामने आना चाहिए

आखिर हत्यारी कोचिंग की जरूरत क्या है? कोचिंग तो किसी व्यक्ति का निजी होगा।यह गर्वनमेंट का तो लगता नहीं। तो इसके लिए कोई घटना इतने बड़े देश में कहीं किसी का भी लापरवाही से हो, सिस्टम कैसे दोषी हो गया? सिस्टम इस घटना का जांच करवायेगा। और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार और कोचिंग संस्थान वालो को केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं कोई मारे या जीए उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कई दूसरे कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में चला रहे जानलेवा लाइब्रेरी। अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो और अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। सरकार और कोचिंग संस्थान वालो को केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं कोई मारे या जीए उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कई दूसरे कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में चला रहे जानलेवा लाइब्रेरी। अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो और अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। ऐसे समय में हमें आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानूनी लाए और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से भी इस पर सुझाव लिया जाए। रेगुलेटर द्वारा कोचिंग संस्थानों की फीस पर भी नजर रखी जाए। किसी जमाने में जीनियस से जीनियस स्टूडेंट के भी 90% से ऊपर नंबर नहीं आते थे, आज साधारण बुद्धि वाला भी 99% नंबर ले आता है, यह सब खेल कोचिंग सेंटर ओर प्राइवेट स्कूलों वालों का है, पेपर लीक, परीक्षा सेंटर और रिजल्ट बनाने वालों से इनकी मिली भगत रहती है। कोचिंग सेंटर के कारनामों का काला चिट्ठा देश के सामने आना चाहिए।

-प्रियंका सौरभ

बेसमेंट में तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक को पता नहीं था कि बेसमेंट में पानी भरने की समस्या आ सकती है। एक कोचिंग की बेसमेंट में नौजवान पढ़ाई कर रहे थे, जब अचानक घुसे तेज पानी ने मौत का रूप धर लिया। बहुत से लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन तीन नौजवान इस हादसे में मारे गए। कुछ दिन पहले दिल्ली के ही एक इलाके में बारिश के दौरान करंट दौड़ने से एक नौजवान की मौत हो गई थी। इन दोनों घटनाओं ने इस तरफ ध्यान खींचा कि देश के अलग-अलग इलाकों से राजधानी दिल्ली में आए स्टूडेंट किन हालात में जीवन बसर कर रहे हैं? दिल्ली ही नहीं देश भर के सभी कोचिंग सेंटर कोरे हवाबाजी है। कितने दूध के धुले हुए हैं आप ये बात सिर्फ इस तथ्य से साफ हो जाती है कि आपके पास बेसमेंट में कोचिंग चलाने का कोई परमिट नहीं है, फिर भी आप बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हैं ।नॉर्म्स साफ नहीं हैं, और आपके पास एनओसी नहीं हैं इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि आप खुद के नियम बना लो।एथिक्स कहती कि व्यक्तिगत नैतिकता और प्रशासनिक नैतिकता के बीच में अस्पष्टता होने पर एक जिम्मेदार व्यक्ति को प्रशासनिक नैतिकता को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए।

कहाँ गया अब ये वाला ज्ञान? जिस कोचिंग में घटना हुई उसमें तो सिर्फ 30 बच्चे बेसमेन्ट में बैठे थे।अन्य कोचिंग में तो 2000-2500 बच्चे बेसमेंट में बैठते हैं। यही घटना अगर वहां होती तो कोचिंग में होते तो क्या होता। सचमुच यह मनुष्य और मनुष्यता का पाषाणयुग है। सरकारों, राजनेताओं, अफसरों और व्यापारियों का लेनदेन युग। एक घराट की तरह इनकी नृशंसता और स्वार्थ के पूड़ घूम रहे हैं जिनमें आमजन और देश के युवा पिस रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में एक कार चालक को दोषी ठहराया गया। सरकार का कहना है कि रोड में पानी भरा रहा, एक कार निकली इस वजह से वह पानी हिल गया और बेसमेंट में चला गया। दोषी न सरकार है न कोचिंग सेंटर मालिक बल्कि दोषी है कार चालक कि वह सड़क पर कार क्यों चला रहा था। यह है हमारी कानून व्यवस्था और यह है हमारी न्याय व्यवस्था। इस घटना ने भारत की राजशाही, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और जूडीशियरी सबको एक साथ नंगा कर दिया है। यहाँ एक आम आदमी, एक आम युवा की जान की कीमत शून्य होती है। सब सो रहे हैं और अंधेर नगरी चौपट राजा की भाँति जब कभी ऐसी कोई घटना होती है तो जनता में से ही किसी एक को पकड़ कर सजा सुना दी जाती है। गनीमत है बच्चों के पैरेंट्स को जेल नहीं भेजा कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए क्यों भेजा। न वह पढ़ने भेजते न मृत्यु होती।

अवैध बिल्डिंग बनती है, तो बुल्डोजर चलता है। क्याकोचिंग सेंटर में भी बुलडोजर चलेगा? आखिर क्यों देश भर में कोचिंग की जरूरत है? क्यों हम इन होनहार बच्चों के लिए ढंग के हॉस्टल नही बनवा सकते। आखिर कितना खर्च होगा या कितने संसाधन लगेंगे इसमें ? ये बच्चे हमारे देश के भविष्य नियंता हैं लेकिन हमारी प्राथमिकता में तभी आयेंगे जब ये किसी बड़े पद पर पहुंच जाएंगे। विडंबना ये है कि यही सिस्टम इन्ही बच्चों को बड़े पदों पर पहुंचने के बाद अपनी असंवेदनशीलता में घेर लेता है जहां ये अपना स्वयं का संघर्ष तुरत फुरत भूल जाते हैं। प्रशासन को मैनेज करने वाले आईएएस अफसरों में से आधे से अधिक ने 10 -15 वर्ष पहले इन्ही बच्चों की जिंदगी जी होगी, लेकिन फिर भी वे इन बच्चों के लिए कुछ कर पाने में या तो समर्थ नहीं हैं, या इसमें इनकी रुचि नहीं है, उनका स्वयं का अतीत भी उनकी प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहा है। आखिर हत्यारी कोचिंग की जरूरत क्या है? कोचिंग तो किसी व्यक्ति का निजी होगा।यह गर्वनमेंट का तो लगता नहीं।तो इसके लिए कोई घटना इतने बड़े देश में कहीं किसी का भी लापरवाही से हो, सिस्टम कैसे दोषी हो गया? सिस्टम इस घटना का जांच करवायेगा। और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।

सरकार और कोचिंग संस्थान वालो को केवल पैसा चाहिए और कुछ नहीं कोई मारे या जीए उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कई दूसरे कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में चला रहे जानलेवा लाइब्रेरी। अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो और अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। ऐसे समय में हमें आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानूनी लाए और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से भी इस पर सुझाव लिया जाए। रेगुलेटर द्वारा कोचिंग संस्थानों की फीस पर भी नजर रखी जाए। किसी जमाने में जीनियस से जीनियस स्टूडेंट के भी 90% से ऊपर नंबर नहीं आते थे, आज साधारण बुद्धि वाला भी 99% नंबर ले आता है, यह सब खेल कोचिंग सेंटर ओर प्राइवेट स्कूलों वालों का है, पेपर लीक, परीक्षा सेंटर और रिजल्ट बनाने वालों से इनकी मिली भगत रहती है। कोचिंग सेंटर के कारनामों का काला चिट्ठा देश के सामने आना चाहिए।

-प्रियंका सौरभ

क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा : आप में स्वयं को पहचानने का एक प्रयास

इसे युगांतरकारी कदम कहा जाना चाहिये या अपनी भूमि, अपनी मिट्टी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी प्रयास। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन-अध्यापन, लेखन-पठन पर विशेष रूप से केंद्रित किया गया है वह अपने आप में स्वयं को पहचानने का एक प्रयास है। हम पिछले दशकों में अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा पद्धति में हम स्वयं को ही भूल चुके थे। यूजीसी द्वारा नई युवा, छात्र पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के अनेक सार्थक व सकारात्मक प्रयास किए जा रहें हैं। विगत दो सौ वर्षों में भारत में चल रही शिक्षा पद्धति ने हमसे हमारा राष्ट्रीय गौरव भाव छीनकर हमें आत्म ग्लानि, व हीनता के भाव से भर दिया था। अब विषय चाहे कोई भी हो, सभी में भारतीयता से जुड़े हुए विषयों का समावेशन आत्म गौरव के भाव को बढ़ाता है।

मैकॉले की शिक्षा पद्धति से हमारी विमति-असहमति दशकों पूर्व से चल रही थी। असहमति के स्वर थे किंतु इस असहमति का निराकरण नहीं हो पा रहा था। गणित, चिकित्सा विज्ञान, योग विद्या, शस्त्र निर्माण, रसायन विज्ञान, वैमानिकी, कृषि विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, न्याय, दर्शन, खगोल विज्ञान, ज्योतिष आदि आदि कई विषयों में हमारी समृद्ध, बलशाली व गौरवशाली विरासत हमें मिली है। हमें हमारी विरासत से सतत वंचित किया गया था। शिक्षा-विद् सतत इस बात को कह रहे थे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति हमें दीन-हीन स्थिति में ले जा रही है, किंतु उनके स्वर अनसुने ही रह रहे थे। मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को समाप्त करने के संपूर्ण प्रयास किए थे। अंग्रेजों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि इस ज्ञान परंपरा के प्रवाह चलते रहने से वे हमें अपना गुलाम नहीं बना पायेंगे। स्वयं के हीनता बोध को समाप्त करने हेतु भी अंग्रेजों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को नष्ट किया।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में जो कार्य सर्वप्रथम होना चाहिये थे वह अब हो रहा है। हमारी ह्रस्वह्व आधारित शिक्षा पद्धति हमें अब मिल रही है।

शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है और शिक्षकत्व क्या है? विशुद्ध भारतीयता अर्थात सनातन स्वमेव ही शिक्षण को व्यक्त करता है। शिक्षण में शिक्षा और शिक्षकत्व के सभी तत्त्व समाहित हो ही जाते हैं। तनिक विस्तार से और तथ्यपूर्वक समझने हेतु यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 33 वें मंत्र को समझते हैं -

आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुषकरमस्त्रजम्।
यथेह पुरुषो-सत।।

महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस मंत्र की व्याख्या की है -ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान पुरुष और स्त्रियों को चाहिए कि विद्यार्थी कुमार व कुमारी को विद्या देने के लिए गर्भ की भाँति धारण करें जैसे क्रम क्रम से गर्भ के मध्य देह बढ़ती है वैसे अध्यापक लोगों को चाहिए कि अच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार व कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धि करें तथा उनका पालन करें वह विद्या के योग से धर्मात्मा और पुरुषार्थ युक्त होकर सदासुखी हो। ऐसा अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। वैदिक वाङ्मय में शिक्षक अर्थात आचार्य शब्द के संदर्भ में व्याख्या है- आचार्य वह जो आचरण की शिक्षा दे, सदाचार दे, दुराचार से दूर रखे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा शब्द को भी परिभाषित करते हुए कहा है - शिक्षा वह जिससे मनुष्य की आत्मा, धर्मात्मा बने, व्यक्ति जितेन्द्रिय हो। हमारी वैदिक धरोहर यजुर्वेद के छठे अध्याय के 14 वें मंत्र मे वैदिक शिक्षा पद्धति को क्रमानुसार पाठ्यक्रम रूप में रचा गया है -

वाचं ते शुन्धामि। प्राणं ते शुन्धामि।
चक्षुस ते शुद्धामि। श्रोत्रम ते शुद्धामि।
नाभि ते शुद्धामि। मेध्रम ते शुद्धामि।
पायुम ते शुद्धामि। चरित्राम ते शुद्धामि।

इस मंत्र में आचार्य अपने शिष्य से कहते हैं, मैं नाना प्रकार की शिक्षाओं से तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं, तेरे नेत्र को शुद्ध करता हूं, तेरी समस्त इंद्रियों को शुद्ध करता हूं और इस प्रकार मैं तेरे चरित्र को शुद्ध करता हूं तेरे। वस्तुतः शिष्य का जितेन्द्रिय हो जाना ही शिक्षा को आत्मसात कर लेना ही शिक्षा में भारतीयता है। ऐंद्रिय दृष्टि से जितेन्द्रिय हो जाने को अर्थात विवेकशील हो जाने व शुचितापूर्ण हो जाने को ही सनातन ने प्रमाणपत्र माना है। भारतीयता सनातन की धुरी पर ही घूमती है।

यहाँ प्रश्न यह उपजता है कि, भारतीयता क्या है?! या जब शिक्षा का भारतीयकरण ही हमारी शैक्षिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता है तो ये ह्रशिक्षा का भारतीयकरणह्व है क्या?! जीवन के विविध, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयता की स्थापना या उनमें देशज तत्व को स्थापित कर देना ही भारतीयता है। इस कार्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के तत्त्व का बना रहना ही शिक्षा का भारतीयकरण है। भारतीयता के अनिवार्य व मूल तत्त्व हैं - भूमि, जन, संप्रभुता, भाषा एवं संस्कृति। हमने यहाँ इन पाँच शब्दों के पूर्व भारतीय शब्द का उपयोग नहीं किया है किंतु जीवन के इन तत्वों में भारतीयता का समावेशीकरण और भारतीयता से ही इन शब्दों के सत्व को साधना यही भारतीयकरण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और भारतीयता विषय की मूल अवधारणा को अति संक्षेप या सूक्ष्म रूप में इस प्रकार ही समझा जा सकता है। विस्तार करें तो, अंतःकरण की शुचिता, बाह्य शुचिता, सात्विकता का सातत्य बनाये रखना और इनसे आनन्दमय रहना है। देशज भारतीय जीवन मूल्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना और उनकी सतत रक्षा ही सच्ची भारतीयता की कसौटी है। संयम, अनाक्रमण, सहिष्णुता, त्याग, औदार्य, रचनात्मकता, सह-अस्तित्व, बन्धुत्व, सर्व समावेशी, सर्व स्पर्शी, समरसता, आदि आदि प्रमुख भारतीय जीवन मूल्य हैं जो शिक्षा में समाहित हों यह आवश्यक हैं। स्वदेशी का आग्रह रखते हुए हम वैश्वीकरण के न केवल अग्रदूत बनें अपितु वैश्वीकरण करण को अपने स्वभाव में स्थापित किए रहें यह भी भारतीयता या सनातनता है। वस्तुतः भारतीय शिक्षा पद्धति या वैदिक शिक्षण ही हमें वह वैचारिक आधार देता है जिस आधार पर स्थिर होकर हम देशज के आग्रह के साथ वैश्विक होते भी हैं और विश्व को भारतीयता में ढलने का संदेश भी देते हैं। इस उपक्रम के फलस्वरूप वैदिक धर्म में विश्व का कितना ध्यान आकृष्ट हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। पर अत्यधिक बल देता है। हमारी शिक्षा में विश्वबंधुत्व का भाव समूचे विश्व में हमारी भारतीयता का द्योतक बन हमारा वैचारिक नेतृत्व करता है। विश्वबंधुत्व का यह अविरल, अविचल अद्भुत और उद्भट भाव हमें हमारी आध्यात्मिकता मात्र से मिलता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है- ह्यह्यभारतीयता आध्यात्मिकता की तरंगों से ओत प्रोत रहने वाला और एक अविभाजित रहने वाला तत्त्व हैह्व। तो, यहाँ से हम समझ समझ सकते हैं कि भारतीयता का अनिवार्य तत्त्व आध्यामिकता है। इस आध्यामिकता से ही युगों युगों से हमारी शिक्षा पद्धति सिद्ध रही है और विश्वगुरु के आसन पर एक बड़े ही दीर्घ कालखंड तक विराजित रहे हैं। वसुधैव कटुम्बकम् की अवधारणा

मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को समाप्त करने के संपूर्ण प्रयास किए थे। अंग्रेजों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि इस ज्ञान परंपरा के प्रवाह चलते रहने से वे हमें अपना गुलाम नहीं बना पायेंगे।

अर्थात् संपूर्ण विश्व को परिवार मानने का व्यापक मानस भारतीयता का और भारतीय शिक्षा का मूल तत्त्व है - **अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।**
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

यह मेरा है, यह पराया है, ऐसे विचार तुच्छ या निम्न कोटि के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले व्यक्ति समूचे विश्व को ही कुटुंब मानने का आचरण स्थिरता से धारण किए रहते हैं। शिक्षण में भारतीयता ही भारतवंशी के मानस में यह विचारतत्त्व स्थापित करती है कि -

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित दुःख भाग्भवेत॥

शिक्षा में भारतीयता ही तो है जो हमें हमें अपने स्थान, ग्राम, जनपद, प्रांत, राष्ट्र से ऊपर उठाकर हमसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम् का उद्घोष कराती है।

घूँघट की बगावत

04 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

भात त्रासदियों का देश है। यहां कभी संसद के भीतर असदी होती है तो कभी संसद के बाहर। कभी हाथरस में त्रासदी होती है तो कभी केरल के वायनाड के चूरलामाला इलाके में कहीं कोई भगदड़ से मरता है तो कहीं कोई भूस्खलन से लेकिन इन त्रासदियों के लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाता।

भारत त्रासदियों का देश

मंगलवार को तड़के हुई वर्षा और भूस्खलन वायनाड के चार गांवों के लिए अमंगल लेकर आया।

अचानक पानी का बहाव बढ़ा और पहाड़ों ने धसकना शुरू कर दिया। पहाड़ों के मलबे ने पहाड़ों की तलहटी में बसे चार गांवों को देखते ही देखते श्मशान में बदल दिया आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक हादसे में 174 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है।

भात त्रासदियों का देश है। यहां कभी संसद के भीतर असदी होती है तो कभी संसद के बाहर। कभी हाथरस में त्रासदी होती है तो कभी केरल के वायनाड के चूरलामाला इलाके में कहीं कोई भगदड़ से मरता है तो कहीं कोई भूस्खलन से लेकिन इन त्रासदियों के लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाता। गनीमत ये है कि केरल सरकार ने चूरलामाला की त्रासदी के बाद राज्य में दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस हादसे के बाद ऐसा निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज है और केरल में नहीं। मंगलवार को तड़के हुई वर्षा और भूस्खलन वायनाड के चार गांवों के लिए अमंगल लेकर आया। अचानक पानी का बहाव बढ़ा और पहाड़ों ने धसकना शुरू कर दिया। पहाड़ों के मलबे ने पहाड़ों की तलहटी में बसे चार गांवों को देखते ही देखते श्मशान में बदल दिया आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक हादसे में 174 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। आपदस्त इलाके के पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन ने प्रियनका बाड़ा भी पीड़ितों तक पहुँचने के लिए तैयार बैठे रहे लेकिन राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने उन्हें खराब मौसम की वजह से वहां जाने से रोक दिया। आपदाएं कहकर नहीं आती न दिल्ली में और न हाथरस में और न वायनाड में तमाम त्रासदियों यानि आपदाओं के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम प्रकृति के खिलाफ खड़े होकर उसे लगातार उसे चुनौतियाँ दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति सबसे अधिक बलवान होती है। उससे नहीं जूझा जा सकता। हमेशा की तरह इन त्रासदियों के पीड़ितों के बीच माननीय नहीं गए। वे खुद इस समय सबसे बड़ी सियासी आपदा से जूझ रहे हैं। वे मणिपुर नहीं गये, हाथरस नहीं गए। जाकर करेंगे भी क्या? उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। वे भले ही अपने आपको भगवान का अवतार मानते हो लेकिन वे अवतार तो नहीं है। वायनाड त्रासदी में फंसे लोगों की सेवा में सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जवान लगे है। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं है। होता तो भी शायद वो कुछ कर नहीं पत्ता क्योंकि आजकल संघ ने सेवा कार्यों से अवकाश ले रखा है। संघ प्रमुख इन दिनों भाजपा को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखण्ड में बचाने में लगे है। केरल में डबल इंजिन की सरकार नहीं है। केरल सरकार भी मुमकिन है कि पीड़ितों को अपेक्षित सहायता न पहुंचा पायी हो, लेकिन केंद्र की सनातनी सरकार ने भी वायनाड के पीड़ितों के लिए अपना खजाना नहीं खोला। ये खजाना तो सरकार को समर्थन देने वाली टीडीपी और जेडीयू को मिनिमम समर्थन मूल्य देने के लिए खुलता है। मैंने हाल ही में कहा था की हमारे देश में मानव जीवन की कोई कीमत तय नहीं है। हम सब कीड़े-मकोड़े है। सरकार त्रासदियों के समय मरने वालों को 50 हजार रुपए दे वा पांच करोड़ रुपये, ये उसकी मर्जी है। सिकेरल वाले तो दिल्ली की आंख की किरकिरी हमेशा से रहे हैं। केरल ने आजतक भाजपा का साथ नहीं दिया ऐसे में दिल्ली वायनाड के पीड़ितों को सहायता कैसे दे सकती है? वायनाड से जो तस्वीरें आ रही हैं, वे हृदयविदारक है। लोग कीचड़ में, मलबे में दबे हैं। इन लोगों को मदद की जरूरत है। जिन अभागों तक मदद नहीं पहुँच सकी वे मारे जा चुके हैं। लेकिन हमारा देश हमारी संसद, चायनाड त्रासदी के मुकाबले दिल्ली की त्रासदी पर सियासत में उलझी हुई है।

मुझे वायनाड की तस्वीरें देखकर महाराष्ट्र का लातूर याद आ रहा है। 1993 में भूकंप ने लातूर को तबाह कर दिया था। 2024 में भूस्खलन चायनाड के चार गांवों को जमीदोज कर दिया है। मुमकिन है कि ये हादसा इस इलाके का प्रारब्ध हो और मुमकिन है कि इस हादसे के लिए केरल की राज्य सरकार जिम्मेदार हो केरल में भले ही सनातनियों की सरकार नहीं है लेकिन उसे लोगों के सुख-दुःख का पता है। केरल सरकार ने दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वैसे ये राष्ट्रीय शोक है। इस हादसे पर संसद में उसी तरह श्रद्धांजलियाँ अर्पित की जानी चाहिए जिस तरह पिछले दिनों दूसरे मृतकों के लिए किया गया था। प्रकृति का रौद्र रूप हमने हिमाचल में भी देखा है इसलिए हम चाहते हों कि वर्षा ऋतु में आपदाओं से निबटने के लिए एक समान और व्यापक नीति बनाई जाना चाहिए। मैं वायनाड की त्रासदी से बुरी तरह आहत हूँ, लेकिन मेरे वा आपके दुखी होने से क्या हासिल? दुखी तो सरकारों को होना चाहिए। सदन में इस त्रासदी पर कोई 'काम रोको प्रस्ताव लेकर आये बहस हो, सरकार बताये कि उसने आपदाग्रस्त राज्यों के लिए क्या राणनीति बनाई है? सरकार आपदाग्रस्त राज्यों के साथ पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर मदद करने को आगे आए। सरकार पीएम केयर फंड से पैसे निकालकर हिमाचल और केरल की मदद करे।

साभार: राकेश अचल

नीट यूजी-2004 पेपर लीक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय करीब 24 लाख छात्रों के लिए राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट-यूजी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। हालांकि 23 जुलाई को आए फैसले का मानवीय पक्ष यह हे कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 लाखअभ्यर्थियों को होने वाली परेशानी को प्राथमिकता दी है। इसके बावजूद शीर्ष अदाल का फै सला भारत में परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हाल के दिनों में देश में विभिन्न रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हासेने और सन्देह के घेरे में आने के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं।

परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता शीर्ष अदालत का निर्णय

नीट यूजी-2004 पेपर लीक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय करीब 24 लाख छात्रों के लिए राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट-यूजी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। हालांकि 23 जुलाई को आए फैसले का मानवीय पक्ष यह हे कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 लाखअभ्यर्थियों को होने वाली परेशानी को प्राथमिकता दी है। इसके बावजूद शीर्ष अदाल का फै सला भारत में परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हाल के दिनों में देश में विभिन्न रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हासेने और सन्देह के घेरे में आने के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। निश्चितरूप से सुनहरे भविष्य की आस में रात-दिन एक करने वाले प्रतियोगियों के साथ यह अन्याय बेहद कष्टदायक है। जो प्रतिभागियों का विश्वास व्यवस्था से उठाता है। नीट-यूजी-2024 की परीक्षा गत पांच मई को हुई थी। इसमें करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए 4 जून को इसका रिजल्ट आया था जिस पर सवाल उठे। परीक्षा में 67 छात्र टॉप कर गए। सभी को 720 में से 720 नंबर मिले। ऐसापहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने सौ फीसदी नंबर प्राप्त किए। इसके बाद मामले तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां भी की हैं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है।

निः संदेह गाहे-बगाजे होने वाले परीक्षा घोटाले ने केवल शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं, बल्कि शिक्षा और कैरियर के नाजुक मोड़ पर खड़े युवा उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित भी करते हैं। भारत एक युवाओं का देश है। ऐसे में जनसांख्यिकी लाभांश का सदुपयोग करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इस घटनाक्रम के बाद सरकार को परीक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने और युवाओं की आकांक्षाओं को संबल देने के लिए इस क्षेत्र में सुधारों को वरीयता देनी चाहिए। निःसन्देह मेडिकल प्रवेश परीक्षा के मामले के निस्तारण में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता की सराहना की जानी चाहिए। बड़ी संख्या में याचिकाएं दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के लिए दायर किये जाने के बावजूद, लाखों छात्रों के हित एवं वक्त की जरूरत के अनुसार, कोर्ट ने तार्किक फैसला दिया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि किसी गड़बड़ी से परीक्षा किस सीमा तक प्रभावित हुई। कोर्ट ने इस बावत ठोस एवं तार्किक पक्ष को प्राथमिकता दी। साथ ही परीक्षा के सामाजिक पक्षों को भी ध्यान में रखा। निश्चित रूप से जिन परीक्षार्थियों का चयन हो चुका था, उन्हें पुनः परीक्षा देने के लिए बाध्य करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। परीक्षाओं की

विश्वसनीयता को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारें चिंतित भी हैं। नीट-यूजी के मामले में केन्रद सरकार ने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। नया कानून लागू करने के साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नियंत्रण करने के लिए नया कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी पेपर लीक से जुड़े कानून बनाए हैं। निःसंदेह लाखों छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था संदेहमुक्त होनी चाहिए। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। अन्यथा छात्रों का व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से बनाए गए कानूनों में प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पर्चा लीक के दोषियों को सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब सवाल यह भी उठता हैकि क्या हर राज्य में अलग-अलग कानून बना देने से पेपर लीक मामलों पर अंकुश लग पाएगा। क्या ये कदम छात्रों और अभिभावकों की परेशानियों को दूर करने के लिए काफी हैं। हमें समझना होगा यह कवायद मात्र रोग के लक्षणों का उपचार करना है। मूल समस्या कहीं अधिक गहरी है और इसकी जड़ों पर प्रहार करने की जरूरत है। सुनिश्चित करना होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता कायम रखी जाए। हर महत्वपूर्ण संस्थान और एजेंसी के कार्य तभी उत्तम स्तर के होंगे, जब सुयोग्य व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने संबंधी कानूनों पर कड़ाई से अमल सुनिश्चित करना जरूरी है। फिलहाल इस मामले में सीबीआई द्वारा तत्परता से की गई कार्रवाई और संदिग्धों की गिरफ्तारी उन लोगों में भय पैदा करेगी, जो लम्बे अरसे से परीक्षा लीक के काले धंधे में धंसे हुए थे। शासन-प्रशासन की सख्ती एवं समय रहते कार्रवाई किसी भी क्षेत्र में शुचिता स्थापित करने में सहायक हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि नीट-यूजी-2024 पेपर लीक घटना पटना और हजारीबाग में हुई। केन्द्री अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आगे की जानकारी उजागर करने के लिए पेपर ली के मामले में अपनी जांच जारी रखेगी। कोर्ट के वयवहारिक फैसले के बावजूद इस विवाह ने हमारी शैक्षिक एवं परीक्षा प्रणाली के भीतर व्याप्त विसंगतियों को भी उजागर किया है। फिलहाल मुख्य न्यायधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ की यह टिप्पणी कि लीक परीक्षा प्रणाली का उल्लंघन नहीं है, एक अस्थायी राहत जरूर प्रदान करता है। लेकिन इस सिस्टम में अंतर्निहित कमजोरियों को संबोधित किया जाना जरूरी है। इसके बावजूद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए और आई आईटी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार बिहार के हजारी बाग और पटना में लीक महत्वाकांक्षी चिकित्सा पेशेवरों के लिए होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजन के तौर-तरीकों की विश्वसनीयता पर तो प्रश्न उठाते ही हैं प्रभावित छात्रों के मामलों को निबटाने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पर नयायालय की निर्भरता समस्या के दीर्घकालीन समाधान के बजाय एक कामचलाऊ दृष्टिकोण को ही दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर गत जून माह में यूजीसी नेट परीक्षा रद होना भी चिन्ताओं को और बढ़ा देता है।

केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय को अज्ञात सुत्रों से मिले तथ्यों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह काररवाई की थी। हालांकि यह कदम छात्रों के हितों की तात्कालिक रक्षा की दृष्टि से सार्थक है लेकिन यह घटनाक्रम हमारी परीक्षातंत्र के बुनियादी ढांचे की कमजोरी को ही उजागर करता है। कह सकते हैं कि परीक्षा तंत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर ऐसे तदर्थवाद एवं पादर्शिता की कमी छात्र समुदाय में अविश्वास एवं चिन्ता को बढ़ाते हैं। फिलहाल हाल की ये घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा परीक्षाएं आयोजित करने वाले तंत्र के ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत को बताती है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि एनटीए की संरचना की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की जाएगी, निश्चित रूप से यह संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में एक उचित कदम है। हालांकि इसके साथ ही परीक्षाओं में सुरक्षा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए मजबूत उपायो को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिल्ली को लंदन, टोक्यो या न्यूयॉर्क से मुकाबला करना होगा और यह तभी संभव है, जब यहां बुनियादी ढांचे पर काम किया जाए।

शहरों में नीतिगत और ढांचागत बदलाव अपरिहार्य

शहरी ढांचे की बेहतरी या नवीनीकरण का काम मूलतः नगर निकायों का है, लेकिन संबंधित विभागों में जरूरी समन्वय बन ही नहीं पाता। दिल्ली में ही जल आपूर्ति का मामला दिल्ली जल बोर्ड के पास है, तो जल निकासी की व्यवस्था नगर निकाय के हवाले। ऐसे में, जब तक स्थानीय निकायों पर पूरी तरह से समन्वय की जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, तब तक इस तरह की समस्या बनी रहेगी।

इस मसले का समाधान इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य हमने तय कर रखा है। चूंकि योजनागत काम नहीं हो रहा, इसलिए आर्थिक क्षमता से भरे इन क्षेत्रों से हमें उचित फायदा नहीं मिल रहा। हम चाहें, तो मुंबई के धारावी से सबक ले सकते हैं, जहां नवीनीकरण का प्रयास तेज किया गया है। इस तरह के काम हर शहर में क्षेत्रों को चिह्नित करके उचित संदर्भ में किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में मुंबई और दिल्ली महानगर ही आने वाले समय में ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिल्ली को लंदन, टोक्यो या न्यूयॉर्क से मुकाबला करना होगा और यह तभी संभव है, जब यहां बुनियादी ढांचे पर काम किया जाए। दिल्ली, मुंबई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता भी आर्थिक विकास के दौर में ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने के दावेदार हैं। ऐसे में, शहरों में नीतिगत और ढांचागत बदलाव अपरिहार्य है। मंझले और छोटे शहर राजकीय व अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्द्धा से आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक हो रहे हादसे शहरी नियोजन की गंभीर कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। राजेंद्र नगर की घटना में, जिस पुस्तकालय में अचानक पानी भर जाने से तीन छात्र- छात्राओं की डूबकर मौत हो गई, उसे बेसमेंट में चलाने की अनुमति ही नहीं थी। इसी तरह, बीती 22 जुलाई को मध्य दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक नौजवान की इसलिए मौत हो गई, क्योंकि उसने जल भरे रास्ते से बचने के लिए एक लोहे के गेट को पकड़ लिया था, जिसमें खुले तारों की वजह से करंट दौड़ रहा था। पिछले साल मुखर्जी नगर में एक कोचिंग संस्थान में लगी आग में 60 से अधिक बच्चे घायल हो गए थे, जबकि जहां उनको पढ़ाया जा रहा था, वह स्थान छात्रों की संख्या के हिसाब से काफी छोटा था। साफ है, प्रशासनिक चूक बच्चों के जीवन पर भारी पड़ती दिखी है। इस चूक का खामियाजा महज पीड़ित परिवार नहीं भुगतते, बल्कि राष्ट्र को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि किसी भी देश के लिए मानव संसाधन बेशकीमती होता है।

ऐसे क्षेत्रों को तकनीकी शब्दावली में 'कोर सिटी एरिया कहते हैं। इनकी आर्थिक क्षमता काफी अधिक होती है, लेकिन अनियोजित विकास और पुराने बुनियादी ढांचे की वजह से इनकी आबादी की सघनता, क्षमता और जरूरी बुनियादी सुविधाओं में कोई मेल नहीं बैठ पाता। दिल्ली सरकार ने ही पिछले दिनों एक अध्ययन के हवाले से बताया था कि राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काफी निवेश की जरूरत है। देखा जाए, तो बारापुला, नजफगढ़ और यमुना पार के इलाके को तीन अलग-अलग भागों में बांटकर जल निकासी की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। अभी इन तीनों इलाकों की ल-निकासी व्यवस्थाओं में कोई सामंजस्य नहीं है। यहां प्राकृतिक जल निकासी से आंखें मूंद ली गई

सवाल उठाए जाते हैं कि इस तरह के व्यवस्थागत बदलाव के लिए पैसे कहां से आएंगे? वास्तव में, हमारे पास पैसों की उस तरह कमी नहीं है, जितनी बताई जाती है। जिस तरह से सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांटती हैं, उसका अगर एक हिस्सा ही ऐसे ढांचागत कार्यों में नियमित रूप से खर्च किया जाए, तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। मुफ्त की रेवड़ियों का ही असर है कि जनहित सेवाओं के संचालन अथवा प्रबंधन में जिस तरह पैसे खर्च करने की जरूरत होती है, उतना सरकारों के पास नहीं बच पाता और उनको केवल आपात स्थिति के लिए अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। राजेंद्र नगर हादसे में ही घटना के बाद तमाम तरह की कमियों की बात सामने आई है। आलम यह है कि जल व्यवस्था को ही दुरुस्त करने के लिए आवश्यक पाइपों की मरम्मत और प्रतिस्थापना का काम नियमित तौर पर नहीं हो रहा, जबकि यह आवश्यक माना जाता है।

बहरहाल, ऐसे मसलों पर किसी सियासी आरोप-प्रत्यारोप में उलझे बिना हमें यही सुनिश्चित करना है कि इसका उचित समाधान हो। यह तय करना ही होगा कि कोई भी अव्यवस्था किसी की जान पर भारी न पड़े। इसके लिए हमें ह्यअर्बन रिन्यूअल पॉलिसी', यानी शहरों के नवीनीकरण की नीति बनानी होगी। वास्तव में, आज भीड़भाड़ वाले अनेक क्षेत्र शहरों के मध्य में आ गए हैं, जबकि वहां का बुनियादी ढांचा आज की जरूरत के हिसाब से नहीं है। वहां नियम-कायदों के पालन में भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। लिहाजा, वहां या तो पूरी तरह रद्दोबदल करते हुए नया ढांचा विकसित किया जाए, अन्यथा जरूरत के हिसाब से मौजूदा ढांचे में ही अपेक्षित सुधार किए जाने चाहिए।

अर्बन रिन्यूअल पॉलिसी' के फायदे यूरोपीय देशों में खूब देखे गए हैं। वास्तव में, दुनिया के तमाम देश ऐसी समस्याओं से जूझते रहे हैं, लेकिन वही इससे सफलतापूर्वक निकल पाते हैं, जो इसके लिए पर्याप्त दृढ़ता दिखाते हैं। यूरोपीय देशों ने समयानुकूल अपने यहां ढांचागत बदलाव किए। इसका नतीजा यह है कि आज वहां सघन आबादी वाले अनियोजित क्षेत्र नहीं दिखते। अच्छी बात है कि इस बार केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर खास ध्यान दिया है। इससे वहां आधारभूत ढांचे पर निवेश हो सकेगा। अब इन राज्यों की आय बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए सभी आकार के शहरों का विकास आवश्यक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में नवीनीकरण पर ज्यादा काम नहीं हो सका है।

कुल मिलाकर, हमें शहरों के आर्थिक विकास का काम नगर निकायों के हवाले करना होगा। उसे ही यह तय करना चाहिए कि कौन-सा क्षेत्र किस गतिविधि के अनुकूल है और इसके लिए कैसा ढांचागत सुधार किया जाए। इस काम में बड़े और छोटे शहरों की अलग-अलग भूमिका होगी। शीर्ष विभागों को इस प्रक्रिया पर निगरानी रखनी चाहिए और जरूरत के मुताबिक समन्वय करना चाहिए। वास्तव में, नगर निकायों की मजबूती ही नगरीय व्यवस्था को बेहतर बनाती है।

कुल मिलाकर, हमें शहरों के आर्थिक विकास का काम नगर निकायों के हवाले करना होगा। उसे ही यह तय करना चाहिए कि कौन-सा क्षेत्र किस गतिविधि के अनुकूल है और इसके लिए कैसा ढांचागत सुधार किया जाए। इस काम में बड़े और छोटे शहरों की अलग-अलग भूमिका होगी। शीर्ष विभागों को इस प्रक्रिया पर निगरानी रखनी चाहिए और जरूरत के मुताबिक समन्वय करना चाहिए। वास्तव में, नगर निकायों की मजबूती ही नगरीय व्यवस्था को बेहतर बनाती है।

घूँघट की बगावत

04 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

कांवड़ियों के गुजरने के बाद रेंगते हुए आगे बढ़े वाहन

करनैलगंज में लग गया था 10 किमी लंबा जाम

लखनऊ। कांवड़ यात्रा के कारण गोंडा करनैलगंज में बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। शनिवार दोपहर वाहनों को रवाना कर दिया गया। इस दौरान करीब 10 किमी लंबा जाम लग गया था। बाराबंकी जिले के रामनगर में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार की मध्य रात्रि से ही गोंडा-लखनऊ मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया था। इसके चलते करनैलगंज में करीब 10 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया। हालांकि, शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वाहनों को रवाना कर दिया गया। छोटे वाहनों व परिवहन निगम की बसों के आवागमन में छूट दी गई थी। बड़े वाहनों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। शुक्रवार की मध्य रात्रि बाराबंकी प्रशासन द्वारा गोंडा के अधिकारियों को सूचना दी गई की लगातार कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के चलते रामनगर, चौकाघाट, घाघरा घाट और मसौली से बाराबंकी के बीच जाम की स्थिति बनी हुई है और गोंडा-लखनऊ मार्ग पर बड़े वाहनों के यातायात पर रोक लगाने के लिए कहा गया। उसके बाद रात्रि करीब 12 बजे करनैलगंज के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने गोंडा लखनऊ मार्ग पर हुजूरपुर तिराहे के निकट बैरियर लगाकर बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। सुबह तक करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। हालांकि दो पहिया, चार पहिया छोटे वाहनों व रोडवेज बसों के आवागमन को बहाल रखा गया है।

मंगलवार सुबह तक बड़े वाहनों की यातायात के बंद रहने की संभावना बनी हुई है क्योंकि सावन माह के तीसरे सोमवार को विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए 24 घंटे पहले इस मार्ग को बंद करने का आदेश पहले से जारी है।

उपजिलाधिकारी भारत भार्गव का कहना है कि छोटे वाहनों को बाराबंकी जिले के चौकाघाट से मोड़ने की व्यवस्था है। जिसके कारण छोटे वाहनों का आगमन नहीं बंद किया गया है। बड़े वाहनों को बंद किया गया था जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।

'केंद्र की कठपुतली के रूप में काम कर रहे राज्यपाल'

राजभवन के नोटिस पर भड़के कर्नाटक के मुख्यमंत्री

बेगलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की आलोचना की और उन पर केंद्र सरकार और भाजपा-जद(एस) द्वारा हेरफेर करने का आरोप लगाया। यह नोटिस मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट वितरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने टवऊअ घोटाले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंन कहा कि मेरी भूमिका वहां नहीं है। मेरी भूमिका कहां है?

सिद्धारमैया ने बताया कि निर्णय लेने के बाद मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को मुझे दिए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने और टीजे अब्राहम द्वारा दायर शिकायत को खारिज करने की सलाह देने के बाद विवरण पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने आगे केंद्र सरकार पर राजभवन का दुरुपयोग करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। सिद्धारमैया ने कहा, ₹राज्यपाल पूरी तरह से केंद्र सरकार, बीजेपी-जेडी(एस) की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस-ासे पहले 26 जुलाई को वकील-कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की याचिका के जवाब में सीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसने मुख्यमंत्री को सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, इस कदम की कर्नाटक सरकार ने व्यापक रूप से आलोचना की, इसके मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल गहलोत से इसे वापस लेने का आग्रह किया।

इससे पहले, मीडिया से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी याचिकाकर्ता टीजे अब्राहम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसमें अब्राहम की आपराधिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया, जिसमें ब्लैकमेल और जबरन वसूली के मामले भी शामिल थे। शिवकुमार ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल नोटिस वापस लेंगे और अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा, परिषद ने राज्यपाल से नोटिस वापस लेने और अब्राहम द्वारा दायर मंजूरी के आवेदन को तुरंत खारिज करने का आग्रह किया।

मुलाकातः

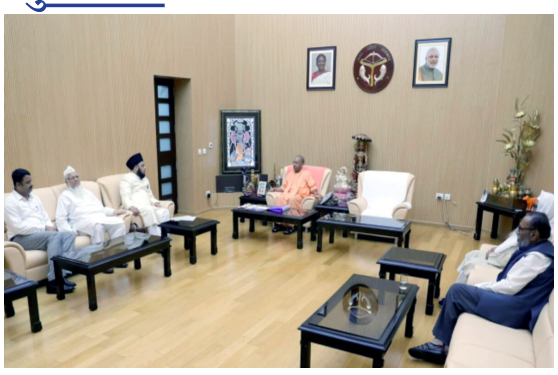

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गत दिनों मंगलवार को पहली बार इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर मुलाकात की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वह उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे।

सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद

मकलोडगंज(हि.प्र.)। बदलते मौसम में अब महंगी सब्जियों ने रसोई घर का जायका बिगाड़ दिया है। अब हरी सब्जियों सहित आलू-टमाटर-प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियां आसमान के भाव छू रही हैं। जिला भर में बारिश के कारण सब्जी वाले खेतों में पानी भरने से सब्जी बाजार में नहीं आ पा रही है। इसलिए सब्जियों की आवक कम हो गई है। जिस वजह से हरी सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। महंगी हुई सब्जी ने रसोई घर के जायके को बिगाड़ दिया है, क्योंकि अब हरी सब्जी के भाव ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं।

कुछ दिन पहले टमाटर 60, सौ रुपए में बिका रहा है, जबकि सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आगामी दिनों में ओर अधिक रेट बढेंगे। वहीं मटर दोहरा शतक जड़ने के बाद भी शांत नहीं है और 250 रुपए बिक रहा है, जबकि शिमला मिर्च 120 से 140, घिया, फूलगोभी 80 और प्याज भी 50 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से जिला कांगड़ा के मु यालय धर्मशाला में बिक रहा है। हरी सब्जियों ने रसोई का जायका पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, जिससे गृहिणियां व लोग परेशान हो गए हैं। दुकानों में मूल्य सूची न लगाने वाले सब्जी दुकानदार नपेंगे जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि मूल्य सूचियां न लगाने वाले सब्जी दुकानदार नपेंगे। इसके लिए तैयारी की है, विशेष अभियान चलाया जाएगा।

पचास शैय्याओं वाला बदहाल आश्रय गृह

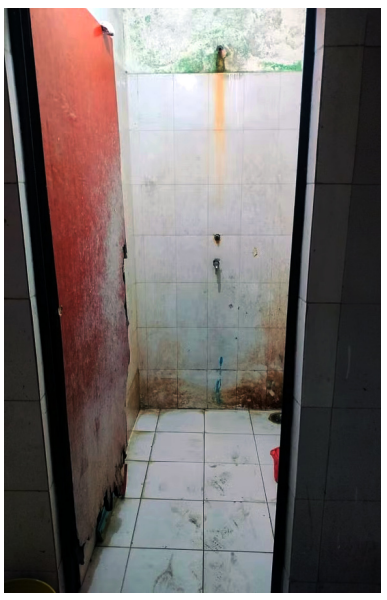

महराजगंज (जीकेबी)। जनपद के विस्मिल नगर में स्थित 50 बेड का आश्रय गृह बदहाल है। शौचालय में दरवाजा ही नहीं है। रोजाना 10-12 लोग शरण लेने के लिए आते हैं, लेकिन एक केयर टेकर को छोड़कर पूरा आश्रय गृह खाली नजर आया। केयर टेकर ने कहा कि सात लोग गृह में रुके हैं। खाना खाने गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत विस्मिल नगर में बने आश्रय गृह में 50 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। आश्रय गृह में पिछले चार माह में रुके लोगों की संख्या पर नजर डाले तो यह पाते हैं कि मार्च में 447 लोग, अप्रैल में 176 लोग, मई में 276 लोग, जून में 277 लोग ठहरे जबकि 10 जुलाई तक 79 लोग ठहरे। केयर टेकर के मुताबिक 10 जुलाई के बाद शरणार्थियों की संख्या मोबाइल पर दर्ज नहीं है साहब रजिस्टर रखकर कहीं चले गए हैं। आश्रय गृह में बने दो शौचालय में एक में दरवाजा नहीं दिखा तो स्नानघर का दरवाजा जर्जर दिखा। दूरभाष पर आश्रय गृह के प्रबंधक रामानुज ने बताया कि खराब होने के कारण शौचालय का दरवाजा निकालकर रख दिया गया है, जबकि एक दरवाजा जर्जर है। जल्द ही बनवाकर लगवा दिया जाएगा। गंदा शौचालय, स्नानघर और हाल में रखे टूटे बेड दुर्व्यवस्था को उजागर कर रहे थे। आश्रय गृह की खिड़कियों पर जाली तो लगा दिखा, लेकिन किसी भी खिड़की पर दरवाजा नहीं था। पूछने पर केयर टेकर राजेश्वर गुप्ता ने बताया खिड़कियों का शीशा टूटने के कारण दरवाजा हटा दिया गया। हाल में लगे दो पंखे खराब हैं। केयर टेकर के मुताबिक कोने में पड़ा कूलर सही है जरूरत पड़ने पर लगा दिया जाता है। यहां रुकने वाले शरणार्थियों के लिए मच्छरदानी आदि की व्यवस्था नहीं है।

आंगनबाड़ी केंद्रों की सेहत खराब, प्री प्राइमरी पढ़ाई बदहाल

महराजगंज (जीकेबी)। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सरकार भले ही गंभीर है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत खराब है। कई केंद्रों में शौचालय, पानी से लेकर बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। वह प्राथमिक स्कूल के भवन में संचालित हो रहे हैं, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अभिभावक भी केंद्रों पर बच्चों को भेजने से कतराते हैं। बच्चों का मन बहलाने के लिए दो वर्ष पहले खिलौने मिले थे जो अब टूट चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं के नाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं। इनमें से अधिकांश पर मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं जो खिलौने बच्चों का मन बहलाने के लिए दिए गए वह टूट गए हैं। प्री प्राइमरी पिपरदेउरा की पड़ताल की गई तो प्राथमिक स्कूल के भवन में संचालित मिला। परिसर में पानी भरने के कारण बंद था। वहीं चिउरहां में भवन जलभराव के कारण बंद रहा। गबडुआ में फरीदा बानों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका निशा देवी मौजूद मिलीं। नामांकित 32 बच्चों में 11 मौजूद मिले। ऊषा देवी ने बताया कि दो वर्ष पहले बच्चों के लिए मिले खिलौने टूट चुके हैं।

जलभराव के कारण कुछ स्कूलों में दिक्कत है वहां कक्षा का संचालन नहीं हो पा रहा है। जहां आज केंद्र बंद मिले हैं, वहां के आंगनबाड़ी से जवाब मांगा जाएगा। समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। -दुर्गेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी

श्रावण मास : कांवड़ का अर्थ एवं उसका महत्व

कांवड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार। अर्थात ब्रह्म यानी परात्पर शिव, जो उनमें रमण करे वह कांवड़िया। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए दूर-दराज से आते हैं और अपने आस-पास के स्थानों से गंगा जल भरते हैं, तत्पश्चात पदयात्रा कर अपने-अपने स्थानों को वापस लौट जाते हैं। इसी यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। फिर चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है, और शिव जी से अपनी और अपनों की सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। कहने के लिए तो ये बस एक धार्मिक आयोजन मात्र है, लेकिन इसका सामाजिक और धार्मिक महत्व बहुत है। इसका सामाजिक सरोकार भी हैं।

कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। जल आम आदमी के साथ-साथ पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों, धरती में निवास करने वाले हजारों-लाखों तरह के कीड़े-मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक तत्व है। उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहां के मैदानी इलाकों में मानव जीवन नदियों पर ही आश्रित है। कांवड़िए जलस्रोत से एक बार जल भरकर उसे अभीष्ट कर्म के पूर्व अर्थात शिवजी को अर्पण करने के पहले भूमि पर नहीं रखते हैं। इसके मूल में भावना यह है कि जलस्रोत से प्रभु को सीधे जोड़ा है जिससे धारा प्राकृतिक रूप से उन पर बनी रहे एवं उनकी कृपा हमारे ऊपर भी सतत धारा के अनुसार बहती रहे जिससे संसार सागर को सुगमता से पार किया जा सके। भोलेनाथ के भक्त यूं तो साल भर कांवड़ चढ़ाते रहते हैं, लेकिन सावन में इसकी धूम कुछ ज्यादा ही रहती है क्योंकि यह मास भगवान शिव को समर्पित है। अब तो उत्तर भारत में खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी व पूर्वी यूपी में कांवड़ यात्रा एक पर्व कुंभ मेले के समान एक महाआयोजन का रूप ले चुकी है। काशी और देवघर में भी कांवड़ यात्रा का खासा महत्व है। पिछले डेढ़ दशक में कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव पर सबसे पहले कांवड़ किसने चढ़ाया और इसकी शुरूआत कैसे हुई। कुछ कथाओं के भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव शिव के नियमित पूजन के लिए पुरा महादेव में मंदिर की स्थापना कर कांवड़ में गंगाजल से पूजन कर कांवड़ परंपरा की शुरूआत की, जो आज भी देशभर में काफी प्रचलित है। कांवड़ की परंपरा चलाने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी श्रावण मास में की जानी चाहिए। पौराणिकता मान्यता है कि कांवड़ यात्रा एवं शिवपूजन का आदिकाल से ही अन्योन्याश्रित संबंध है। महाकवि कालिदास ने हिमालय को शिव का प्रतिरूप बताते हुए इसके सांस्कृतिक, भौगोलिक और धार्मिक महत्त्व को रेखांकित किया है। यों भी कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा के नीर से उसके अभिषेक को तीव्र रूप में प्रतिध्वनित करती है। उत्तर भारत में भी गंगाजी के किनारे के क्षेत्र के प्रदेशों में कांवड़ का बहुत महत्व है। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के लोगों के यहां गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ के तीर्थ पुरोहित जो जल लाते थे और प्रसाद के साथ जल देते थे, उन्हें क-ांवड़िए कहते थे। ये लोग गोमुख से जल भरकर रामेश्वरम में ले जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते थे।दरअसल, यह एक प्रचलित परंपरा थी। लगभग 6 महीने की पैदल यात्रा करके वहां पहुंचा जाता था। इसका पौराणिक तथा सामाजिक दोनों महत्व है। इससे एक तो हिमालय से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण देश की संस्कृति में भगवान का संदेश जाता था। इसके अलावा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की लौकिक और शास्त्रीय परंपराओं के आदान-प्रदान का बोध होता था, लेकिन अब इस परंपरा में परिवर्तन आ गया।

कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व तो जगजाहिर है, लेकिन इस क-ांवड़ यात्रा से वैज्ञानिकों ने उत्तम स्वास्थ्य भी जोड़ दिया है। प्रकृति के इस खूबसूरत मौसम में जब चारों तरफ हरियाली छाई रहती है तो कांवड़ यात्री भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पैदल चलते हैं। पैदल चलने से हमारे आसपास के वातावरण की कई चीजों का सकारात्मक प्रभाव हमारे मनमस्तिष्क पर पड़ता है। चारों तरफ फैली हरियाली आंखों की रोशनी बढ़ाती है। वहीं ओस की बूंदे नंगे पैरों को ठंडक देती हैं तथा सूर्य की किरणें शरीर को रोगमुक्त बनाती हैं। ये यात्रा प्रकृति और मानव के संबंधों में नई उष्मा, निकटता एवं प्रेम को बढ़ाती है। डॉक्टरों के मुताबिक धार्मिक चेतना से मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कांवड़ यात्रा स्वास्थ्यप्रद होती है। पैदल, नाचते-गाते और दौड़ लगाते हुए शिवभक्त जाते हैं। इससे शरीर में खुशी के हार्मोंस जेनरेट होते हैं। व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। पैदल चलने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हार्ट और फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। पवित्र गंगा को स्वर्ग अर्थात पहाड़ों से पृथ्वी अर्थात मैदानी इलाकों में लाने के लिए महान शिव के द्वारा जिस श्रमदान का आयोजन किया गया वह उस समय अत्यंत दुष्कर कृत्य रहा होगा। पर्वतों के बीच गमन करना और श्रमदान करना निश्चित ही कोई सुगम कार्य नही रहा होगा। कितने ही किसान-श्रमिक कर्तव्य की बलिवेदी पर न्योछावर हुए होंगे।

यह बात वह शिव भक्त कांवड़िये आसानी से समझ सकते हैं जो गोमुख या उसके भी ऊपर ऊंचाइयों से जल लाने हेतु पैदल पद यात्रा करते हैं। उसी महान श्रमदान की स्मृति आज भी कांवड़ के विशाल आयोजन में संरक्षित दिखाई पड़ती है। संभवतः हताहत तथा कालकलवित हुए कृषकों व श्रमिकों की आत्मा की शांति की कामना के लिए उसी पवित्र जल से शिव को जलाभिषेक करने की उज्जवल परम्परा का विकास कांवड़ यात्रा मे कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होता है। इस तथ्य से यह भी जाना जा सकता है कि जो जल हमें आज इतनी आसानी से प्राप्त है वह कितना मूल्यवान है। नदियों से दूर-दराज रहने वाले लोगों को पानी का संचय करके रखना पड़ता है। हालांकि मानसून काफी हद तक इनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है तदापि कई बार मानसून का भी भरोसा नहीं होता है। ऐसे में बारहमासी नदियों का ही आसरा होता है, इसके लिए सदियों से मानव अपने इंजीनियरिंग कौशल से नदियों का पूर्ण उपयोग करने की चेष्टा करता हुआ कभी बांध तो कभी नहर तो कभी अन्य साधनों से नदियों के पानी को जल विहिन क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आबादी का दबाव और प्रकृति के साथ मानवीय व्यभिचार की बदौलत जल संकट बड़े रूप में उभर कर आया है। धार्मिक संदर्भ में कहें तो इंसान ने अपनी स्वार्थपरक नियति से शिव को रूष्ट किया है। कांवड़ यात्रा का आयोजन अति सुन्दर बात है। कांवड़ यात्रा में शामिल हर कांवड़िए को इस महत्वपूर्ण यात्रा महत्ता व अंतर्निहित संदेश को समझना होगा। प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप हैं। वास्तव में, धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर और नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत-खलिहानों की सिंचाई करें और अपने निवास स्थान पर पशु-पक्षियों और पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। विभिन्न धमार्चार्यों का भी यही मत है शिव की सच्ची उपासना केवल पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन से ही संभव है। कलियुग में विषपान करने के लिए शिव ने ही पौधों का रूप लिया है। गंगा सहित सभी नदियां शिव की तरह जीवनदायिनी हैं। इन्हें बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।

माँ आशा देवी स्मृति सम्मान और मुंशी प्रेमचंद शिरोमणि सम्मान बिहार के रूपेश को

सिवान। बिहार के युवा साहित्यकार रूपेश कुमार को साहित्य के क्षेत्र मे विशेष उपलब्धि के लिए 25 जुलाई को लखनऊ में सादे समारोह मे **माँ आशा देवी स्मृति सम्मान- 2024** एव **मुंशी प्रेमचंद शिरोमणि सम्मान - 2023** से नवाजा गया । यह सम्मान प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन यू.पी /निहारिका साहित्य मंच के तत्वावधान मे दिया गया। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अब्दुल अजीज सिद्दिकी एव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह निहारिका साहित्य मंच की संस्थापिका डॉ रीमा सिन्हा के कर कमलो द्वारा सम्मानित किया गया ।

इनकी चार एकल संग्रह विभिन्न सामाजिक, स-ांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक विषयों पर आलेख प्रकाशित हो चुके है । वर्तमान मे रूपेश विज्ञान के शोध छात्र, शिक्षक एंव प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है लेकिन साहित्य मे इनकी काफी रूचि है रूपेश को शिक्षा के क्षेत्र मे विशेष उपलब्धि के लिए हाल ही मे **राष्ट्रीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान-2024** से भी सम्मानित किया गया । इनकी साहित्यिक/शिक्षा मे अनेकों उपलब्धियों के कारण इनको देश ही नही विदेशों से भी अनेकों सम्मानों से यथा लखनऊ मे भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान, दिल्ली मे कबीर कोहिनूर सम्मान, इंदौर मे अभ्युदय सम्मान इत्यादी सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है । रूपेश के संपादकीय मे भी चार साहित्यिक पुस्तकें आ चुकी है । रूपेश अद्भुत प्रतिभा के धनी है जिसके कारण इनकी रचनाओं को देश- विदेशों के पत्र-पत्रिकाओं में जगह मिल चुकी है । भौतिक विज्ञान का छात्र होते हुए भी साहित्य मे आपका विशेष स्थान है।

यह दिल मांगे मोर

चीर कर सर्द हवाओं का सीना
पार करके बर्फ से ढके पहाड़
भाग गया दुश्मन डर के मारे
सुन कर भारत के वीरों की दहाड़
बर्फ की चट्टानें कठिन चढ़ाई
रोक न सकी वीर जवानों की राह
भारत माता का साया था सर पर
करना था अब दुश्मन को तबाह
वह टाइगर हिल और मश्कोह घाटी
खाली करवाने में लगा दिया था पूरा जोर
आज भी सुनों तो आवाजें आती है
कहती हैं यह दिल मांगे मोर
एक एक ने कईयों को मारा
भारत माता की जय था केवल नारा
आखिरी शब्द थे उनके जो लौट न पाए
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा
कारगिल युद्ध नहीं भूलेगा देश
नहीं भूलेगा अपने वीरों की कुबार्नी
याद बहुत आएंगे जो लौट के न आये
लुटा दी जिन्होंने देश पर अपनी जवानी
घर पर राह देख रहे उनकी
साया उनका हर तरफ नजर है आता
कैसे समझाए अब उन्हें कोई
कि जो चला गया उसको कोई बुला नहीं पाता

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

दोहे

काज धर्म के कीजिए,मिले तुम्हें पहचान।
आए हो तो जगत में,बनो नेक इंसान।
इक दिन जाना छोड़ के,काहे का अभिमान ।
प्यार बांटते तुम चलो,मिल जाए सम्मान।।
सेवा करने से मिले,जग में तुमको मान
अपना सबको मानिए,खास बने पहचान।।
दुनिया में मिलती नहीं,सबको जी पहचान।
जमकर मेहनत कीजिए,करें सभी गुणगान ।।
महकाए संसार को,ऐसा हो किरदार
सबमें भरता जोश जो,सख्स वही दमदार।।
दुख की गठरी को लिए,सुख को करता दूर
प्यार प्रेम को जानिए,सुख मिलता भरपूर।।

सीमा रंगा इन्द्रा

साहित्यऔर संस्कृति का संरक्षण है कविता- संदीप शजर

नव सृजन कला,साहित्य, एवं संस्कृति न्यास और हिन्दी साहित्य अकादमी दिल्ली संभाग द्वारा आयोजित साहित्य अनुष्ठान बहुत ही सफल और शानदार रहा। अन्वेषा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत संगीतमयी माँ वीणा पाणि की वन्दना से शुरू हुआ यह कार्यक्रम संगीत, साहित्य और कला को समाहित किये हुए अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था जिसमें हर विधा और कवि सम्मेलनों की परम्परा में प्रचलित रस की कविताएँ प्रस्तुत की गईं। जहाँ एक ओर कवियों ने हास्य की रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाया तो वहीं ओज पूर्ण रचनाओं से देश के प्रति कर्तव्य बोध भी कराया। डॉ कीर्ति काले द्वारा प्रस्तुत माँ गंगा की महिमा के गीत ने सभागार को गंगा जल की तरह बहुत ही पवित्र सुखद बना दिया। स्वागत और सम्मान की श्रृंखला में डॉ आदेश त्यागी को नूर ए गजल सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया तथा समस्त अतिथियो एवं कवियों को माला, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिह्न के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय गोविन्द गुलशन द्वारा की गई तथा अतिथियों की दीर्घा में अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉ प्रवीण शुक्ल जी, योगराज अरोड़ा प्रधान आर्ष गुरुकुल एटा, राजेश चेतन ओजस्वी कवि,डॉ सुरेश अवस्थी सुप्रसिद्ध कवि, डॉ कीर्ति काले अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री, प्रो ओमनाथ बिमली कुलपति आर्ष गुरुकुल यज्ञतीर्थ एटा एवं हिन्दी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ जैन सुमन उपस्थित रहे। आमंत्रित कवियों में आर्य राजेश यादव, एटा उ. प्र. , ओमप्रकाश कल्याणे, दिल्ली, मंजू शाक्य, दिल्ली, विजय विकास त्यागी व पावनी कुमारी ने काव्य पाठ किया।

कवि आर्य राजेश यादव जी द्वारा-

भारत में रहकर भारत को
ही लगा रहे थे पलीता।
ऐसे दुष्ट दलों का अब
हो रहा खूब फजीता।
मोदी योगी ने इस
राजनीति के मानदंड हैं बदले,
अब एक हाथ में संविधान है
एक हाथ में गीता।।

प्रस्तुत कर खूब तालियाँ बटोरी तो वही कवयित्री मंजू शाक्य द्वारा

सुनो इक संदली मौसम
तुम्हारे मन पे मल देते
तुम्हें पतझड़ में भी
मधुमास के अनमोल पल देते
लकीरों के बदलने से
मुझे हासिल जो होते तुम
खुरचकर हाथ की
सारी लकीरों को बदल देते
पंक्तियों से सदन को
ताली बजाने पर
मजबूर कर दिया

ओमप्रकाश कल्याणे जी द्वारा क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके,

अपने साथी कुत्तों को मार आया हो,
या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से
दूध बनाया हो।
अरे हमारा हर साथी,
तुम्हारी रक्षा के लिए,
रातों तक को जागा है।
और हम में से कोई कुत्ता
बैंकों से कर्जा लेकर
विदेशों को नहीं भागा है।

प्रस्तुत कर व्यंग्य परम्परा को आगे बढ़ाया.।

कवयित्री पावनी कुमारी द्वारा ओजस्वी रचना प्रस्तुत की गई **कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं होता जमाने में,**
किसी दर के भिखारी हम,
किसी दर के भिखारी तुम।

विजय विकास त्यागी ने सुनाया -

खुशनसीब हैं वो जिनके पिता हैं
पिता से बढ़कर कोई आसमान नहीं होता है

स्वागताध्यक्ष के रूप में श्री रमेश चंद्र गुप्ता एवं स्वागत समिति के रूप में संदीप शजर राष्ट्रीय कवि, निधि भार्गव , सीमा रंगा इन्द्रा , विवेक कुशवाहा, इन्द्रेश द्विवेदी कमल सिंह पुंडीर , अनिल शर्मा, अनिल सोलंकी एवं समस्त कार्यकारिणी हिन्दी साहित्य अकादमी दिल्ली संभाग और नवसृजन कला, साहित्य एवं संस्कृति न्यास की उपस्थिति रही।

जातीय जनगणना पर घमासान

भारतीय राजनीति में जाति एक हकीकत तो है ही लेकिन इसकी जड़ें समाज में बहुत ही गहराई तक है। कहा जाता है कि जाति मरने के बाद ही खत्म हो पाती है। क्योंकि धर्म तो आप बदलने का अधिकार रखते हैं लेकिन जाति को नहीं बदल सकते हैं। यही कारण है कि जिन धर्मों में जातियां नहीं थीं वहां भी धर्म परिवर्तन के साथ ही जातियों का अस्तित्व और बोध आ गया है। जहां तक जातीय जनगणना का प्रश्न है। देश में जो भी संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान है उसमें या तो अनुसूचित जातियों का और जनजातियों का है या फिर शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए प्रावधान है जिसे जातियों में ही निहित किया गया है। क्योंकि आज भी लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को उनकी जातियों से आंका जा सकता है। यही कारण है कि बिहार में जातीय सर्वे के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था उसे भले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया लेकिन जाति एक हकीकत है और समाज व्यवस्था में ही नहीं राजनीति में भी आज से नहीं पहले से ही इसका प्रयोग और उपयोग होता आया है। यही कारण है कि चुनावी क्षेत्र में जब किसी को टिकट देने का प्रश्न आता है तो इसकी खोज की जाने लगती है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है। मंत्रियों को बनाने से लेकर विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां भी इसी आधार पर की जाती है जिससे उसे समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। जहां तक जातीय जनगणना का प्रश्न है आजादी के पहले देश में जातीय जनगणना हुई थी उसके बाद संप्रग दो के कार्यकाल में सामाजिक आर्थिक सर्वे के नाम पर भी अप्रत्यक्ष रूप से जातियों की गणना हुई थी जबकि इसका उद्देश्य जातीय जनगणना नहीं था। आज जो भी सरकार की योजनाएं केन्द्र व राज्य में चल रही हैं उसके मूल में 2011 में हुआ संप्रग सरकार के दौरान सामाजिक आर्थिक सर्वे है जिसके माध्यम से लाभार्थी की पात्रता का प्रश्न तय होता है।

कबीरदास ने कहा था 'जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरबार का, पड़ा रहन दो म्यान' संसद भवन में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहस को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा यह कहा जाना कि जो जातीय जनगणना की

जहां तक जातीय जनगणना का प्रश्न है, जब देश में व्यवस्थाएं उस पर आधारित हैं योजनाओं और आरक्षण का आधार बिन्दु वही है तो फिर जातीय जनगणना करवाने में क्या हर्ज है।

बात करते हैं उनकी जाति क्या है? जब मामले ने तूल पकड़ा तो वह यह कहकर बचने की कोशिश करने लगे कि मैने नाम तो लिया नहीं था। वह बेवजह कूद पड़े। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग जितनी भी गाली देना चाहते हैं दें, मैं माफी के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन मैं जातीय जनगणना करवा कर रहूंगा। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्या आप हमारी जाति पूछेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि क्या मुझे नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री रहने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से नहीं धुलवाया गया था?

संसद में जिस प्रकार से जाति को लेकर सत्तापक्ष के सांसद द्वारा राहुल गांधी को इंगित करते हुए टिप्पणी की गई वह बेहद शर्मनाक है और यह दशार्ती है कि कोई सांसद भले ही हो गया हो लेकिन जातीय मानसिकता उसके दिमाग में कूट-कूट कर भरी हुई है। दुःखद यह है कि अनुराग ठाकुर के संसद में इस प्रकार के व्यवहार पर प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई है यानि उनकी प्रशंसा की है। वैसे ही अनुराग ठाकुर को पार्टी में अपने नम्बर बढ़ाने के लिए कुछ भी करना ही पड़ता है। दिल्ली प्रदर्शन और दंगों के दौरान उनका वक्तव्य 'गोली मारो.....।' तो विश्वविख्यात हो गया है। कौन सा व्यक्ति किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। उसका सार्वजनिक व्यवहार किस प्रकार है, इससे ही उस व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए उनका जाति पूछने से सम्बन्धित दो अर्थी संवाद उन्हीं को मुबारक। इसका प्रभाव दूसरे पर कम और उस व्यक्ति पर ही ज्यादा पड़ता है जो इस तरह के वक्तव्य देता है।

संसद की स्थिति किस प्रकार की हो गई है इसका अन्दाजा तो पिछले सत्र में हो गया जब बसपा सांसद दानिश अली के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उससे ही साबित हो गया था कि समाज में कितनी गिरावट आ गई है कि समाज से ही लोग विभिन्न जगहों पर जाते हैं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जहां प्रधानमंत्री दंडवत करके चौखट पर अपना शीश नवाते हो वहां उनके ही लोगो की भाषा यही दशार्ती है कि कथनी और करनी में कितना अन्तर है। वह जाति ही तो है जिसके कारण आज भी कुछ लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर अपनी जाति को सर्वोच्च मानते हुए गर्व महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश में एक सत्तारूढ़ दल का नेता एक दलित पर पेशाब करता है। रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ती है। स्कूल कालेजों और यहां तक कि नौकरियों में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। निर्णायक मंचों पर उनके साथ भेदभाव होता है। जिसके कारण बहुत सी प्रतिभाएं उपयुक्त स्थान नहीं पाती हैं।

जहां तक जातीय जनगणना का प्रश्न है, जब देश में व्यवस्थाएं उस पर आधारित हैं योजनाओं और आरक्षण का आधार बिन्दु वही है तो फिर जातीय जनगणना करवाने में क्या हर्ज है। इससे यही होगा कि जो लोग अपने को जातिगत आधार पर सर्वोच्चता भाव से ग्रस्त है जब असलियत सामने आयेगी तो उनके हक भी प्रभावित होंगे।

झूला-झूलने की परम्परा को लगा ग्रहण

सावन को बहुत पवित्र महीना माना जाता है। मान्यता है कि सावन में माता पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें पाया था। सावन दक्षिणायन में आता है जिसके देवता शिव हैं। इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के महीने में बहुत वर्षा होती है। इसलिये इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है। तुम्हें गीतों में ढालूँगा सावन को आने दो । ऐसे गाने सावन आते ही लोगों की जुबान पर खुद-ब-खुद आ जाते हैं। पहले सावन शुरू होते ही गांव की गलियों से लेकर शहरों तक झूले पड़ते थे। महिलाएं झूला झूलतीं और गाती थीं। सावन व भादो का महीना हमे प्रकृति के और निकट ले जाता है। झूले झूलने के दौरान गाये जाने वाले गीत मन को सुकून देते हैं। झूले गांव के बागीचों, मंदिर के परिसरों में डाले जाते थे।

भारतीय संस्कृति में झूला झूलने की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है। श्री कृष्ण राधा संग झूला झूलते और गोपियों संग रास रचाते थे। मान्यता है कि इससे प्रेम बढ़ने के अलावा प्रकृति के निकट जाने एवं उसकी हरियाली बनाये रखने की प्रेरणा मिलती है। एक दौर था जब लोगों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता था। लड़कियां ससुराल से मायके आती थीं। लेकिन अब ये परंपरा खत्म होती जा रही है। अब न तो झूले पड़ते हैं और न गीत सुनाई देतें है।

सावन शुरू हो गया है लेकिन इसका एहसास ही नहीं हो रहा है। उमंग और खुमारी का संगम इसी महीने में हरियाली तीज पर खत्म होता था। सखियों को सुख-दुख बांटने, साथ बैठकर मेंहदी लगाने की परंपरा फिर गीत गाना सब गुम हो चुका है। बच्चे अब झूले नहीं वीडियो गेम में मस्त रहते हैं। महिला संगठन भी अब किटी पार्टी जैसे आयोजनों तक सीमित हैं। झूले की परम्परा लुप्त होने के पीछे सबसे प्रमुख वजह मनोरंजन के भरपूर साधनों का होना भी हैं।

सावन के आते ही गली-कूचों और बगीचों में मोर, पपीहा और कोयल की मधुर बोली के बीच युवतियां झूले का लुत्फ उठाया करती थीं। अब न तो पहले जैसे बाग-बगीचे रहे और न ही मोर की आवाज सुनाई देती है। अब बिना झूला झूले ही सावन गुजर जाता है।

वन माफियाओं के चलते गांवों में भी बाग-बगीचे नहीं बचे हैं। जहां युवतियां झूला डाल कर झूल सके। अब समय के साथ पेड़ गायब होते गए और उनके स्थान पर बहुमंजिला इमारतों के बनने से आंगन का अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसे में सावन के झूले भी यादें बनकर हमारी परम्परा से गायब हो रहे हैं। जन्माष्टमी पर मंदिरों में सावन की एकादशी के दिन भगवान को झूला झुलाने की परम्परा जरूर अभी भी निभाई जा रही है। आज के समय में सावन के झूले नजर नहीं आने का कारण जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ ही वृक्षों की कटाई हैं।

लोग अब घर की छत पर या आंगन में लोहे के झूले पर झूलकर मन को संतुष्ट कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग सावन के झूलों के लुप्त होने की प्रमुख वजह सुख सुविधा और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि को मान रहे हैं। सावन में झूला झूलना मात्र आनंद की अनुभूति नहीं कराता अपितु यह स्वास्थ्यवर्धक प्राचीन योग भी है। सावन में चारो तरफ हरियाली छाई होती है। हरा रंग आंखों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। झूला झूलते समय श्वांस-उच्छवास लेने की गति में तीव्रता आती है। इससे फेफड़े सुदृढ़ होते हैं। इसके साथ ही झूलते समय श्वांस अधिक भरा, रोका एवं वेग से छोड़ा जाता है। इससे नवीन प्रकार का प्राणायाम पूर्ण हो जाता है जो स्वास्थ्य वर्धक है। झूलते समय रस्सी पर हाथों की पकड़ सुदृढ़ होती है। इसी प्रकार खड़े होकर झूलते समय झूले को गति देने बार-बार उठक-बैठक लगानी पड़ती हैं। इन क्रियाओं से एक ओर हाथ, हथेलियों और उंगलियों की शक्ति बढ़ती है वहीं दूसरी ओर हाथ-पैर और पीठ-रीढ़ का व्यायाम हो जाता है।

गांवों की बुजुर्ग महिलाएं बताती हैं कि सावन आते ही बेटियां ससुराल से मायके बुला ली जाती थीं और पेड़ों पर झूला डाल कर झूलती थीं। त्योहार में बेटियों को ससुराल से बुलाने की परम्परा तो आज भी चली आ रही है। लेकिन जगह के अभाव में न तो कोई झूला झूल पाता है और न ही अब मोर, पपीहा व कोयल की सुरीली आवाज ही सुनने को मिलती हैं। दस साल पहले तक यहां रक्षाबंधन तक झूले का आनंद लिया जाता था। गांव के पेड़ पर मोटी रस्सी से झूला डाला जाता था और सारे गांव की बहन-बेटियां झूलती थीं। अब पेड़ ही नहीं हैं तो झूला कहां डालें। सावन के महीने में नवविवाहित महिलाओं को अपने मायके जाने की परम्परा राजस्थान में तो आज भी चली आ रही है। अब वक्त ने ऐसी करवट ली है कि सावन तो आता है पर अपने रंग नहीं बिखेर पाता। जिस सावन के आते ही नववधु ससुराल से मायके पहुंच जाती थी। अब वैसा सावन नही होता है। झूले की परम्परा लुप्त होने के साथ ही सावन भादों की खुशबू अब कहीं नहीं दिखती है। कुछ स्थानों को छोड़ कर लोग इसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। झूलों के नहीं होने से हमे लोक संगीत भी सुनने को नहीं मिलता है। आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के संग झूला झूलने की बात अब कहीं नहीं दिखती है। आज से दो दशक पहले तक झूलों और मेंहदी के बिना सावन की परिकल्पना भी नही होती थी। झूला झूलने के खत्म हुए रिवाज के लिए गांवों में फैल रही वैमनष्यता भी जिम्मेदार हैं। पहले गांव के लोग हर बहन-बेटी को अपनी मानते थे लेकिन अब जमाना बदल गया है। जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही भक्षक बन जाता है। बाग-बगीचों के खात्मे के साथ जहां मोर-पपीहों की संख्या घटी है वहीं भाईचारे में कमी आई है। नतीजतन झूला-झूलने की परम्परा को ग्रहण लग गया है।

पहले संयुक्त परिवार में बड़े-बूढ़ों के सानिध्य में लोग एक दूसरे के घरों में एकत्रित होते थे। आज बढ़ती एकल परिवार की प्रवृति ने आपसी स्नेह को खत्म कर दिया है। महिलाएं

भारतीय संस्कृति में झूला झूलने की परम्परा वैदिक काल से ही चली आ रही है। श्री कृष्ण राधा संग झूला झूलते और गोपियों संग रास रचाते थे। मान्यता है कि इससे प्रेम बढ़ने के अलावा प्रकृति के निकट जाने एवं उसकी हरियाली बनाये रखने की प्रेरणा मिलती है। एक दौर था जब लोगों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता था। लड़कियां ससुराल से मायके आती थीं। लेकिन अब ये परंपरा खत्म होती जा रही है। अब न तो झूले पड़ते हैं और न गीत सुनाई देतें है।

सामुदायिक केन्द्रो में जाकर पर्व मनाती हैं। शहरों में अब झूले डालने के लिए जगह की तलाश करनी पड़ती है।

अब तो पारम्परिक पहनावा भी आधुनिकता की भेंट चढ़ गया है। अब छुट्टी के दिन लोग परिवार के साथ बाग-बगीचों में जाकर सावन का त्यौहार मनाने की रस्म पूरी करते हैं। वर्षा ऋतु में सावन की खूबियां अब किताबों तक ही सीमित रह गई हैं। अब प्रकृति के साथ जीने की परम्परा भी थमती सी जा रही है।

घूँघट की बगावत

04 अगस्त 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

8

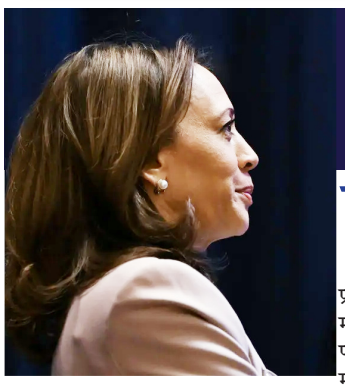

जो बाइडेन ने चुनाव से हटने का फैसला क्यों किया, वह एक अलग चर्चा का विषय है। फिलहाल कमला हैरिस उनके स्थान पर नामांकन हासिल कर लेती हैं तो उनका मुकाबला डेमोक्रेट डॉनल्ड ट्रम्प से होगा। और अगर कमला यह चुनाव जीत लेती हैं तो वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके पहले हिलेरी क्लिंटन भाग्य आजमा चुकी हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी।

दुनिया भर की निगाहें पांच नवम्बर के चुनावों पर

अमेरिकी समाज में प्रगतिशील वाम और मध्यमार्गी डेमोक्रेट के पास 53-54 प्रतिशत मत हैं। इनमें अधिकतर निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग की एकल महिलाएं हैं, जो अपने सीमित संसाधनों के कारण मतदान में हिस्सा नहीं ले पातीं। कमला हैरिस ने पिछले चार वर्षों में अथक परिश्रम, एक महिला को छूने वाले मुद्दों में 'गर्भपात और इमिग्रेशन' पर काम किया है, उससे महिलाओं के एक बड़े वर्ग में कमला हैरिस के प्रति झुकाव बढ़ा है। चुनाव में अभी मात्र 105 दिन का समय शेष है। कमला हैरिस के सम्मुख पार्टी नियमों के अंतर्गत पहले नामांकन हासिल करना है और उसके बाद चुनाव प्रचार में एक बड़े फंड की जरूरत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी फंड में मात्र 910 लाख डालर हैं, जो अमेरिकी चुनाव के लिए अत्यंत अल्प राशि है । हैरिस के दौड़ में आते ही बड़े और छोटे फंड देने वाले आगे आ रहे है। उन्होंने पहले पांच घंटों में खासी रकम जुटाई है। कमला के सम्मुख इस समय सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन के अकस्मात राष्ट्रपति पद की दौड़ में हटने से पैदा हुई परिस्थिति में नामांकन हासिल करने की समस्या है। उनके नामांकन को लेकर पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में बराक ओबामा, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर के रूप में दायित्व निभाने वाली नैन्सी पेलोसी तथा सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पार्टी लीडर और नेता के रूप में दायित्व निभाने वाले चूक शमर ने वार की देर रात तक कमला के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इसके बावजूद कमला एक दर्जन से अधिक डेमोक्रेट राज्यों और स्विंग स्टेट में समर्थन हासिल कर पद के उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं। कमला हैरिस के पक्ष में यह बात भी जाती है कि उन्होंने पिछले चार सालों में अमेरिका के विभिन्न राज्यों में मूल अश्वेत, लैटिन अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, दूर दराज के गांवों में रहने वाले आदिवासी और निर्धन वर्ग के मतदाताओं के साथ साथ पहली बार चुनाव में भाग लेने को आतुर युवक-युवतियाँ को अपने वोट बैंक के रूप में लक्ष्य बनाकर साधा है।

भारतीय मूल की अश्वेत महिला कमला हैरिस राष्ट्रपति हो चुनाव-2024 जीत सकती हैं, बशर्ते डेमोक्रेट एकजुट जाएं और उनके एक वर्ग का महिलाओं के प्रति नजरिया बदल जाए। कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद से एशियाई अमेरिकी, अफ्रीकी अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी खेमों में खुशी की लहर है। कमला ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि 'नामांकन लूंगी और चुनाव भी जीतूंगी।' अमेरिका की दो बड़ी पार्टियों- रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में परंपरावादियों का एक बड़ा समूह है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में संकोच करता है। डेमोक्रेटिक पुरुषों में एक-डेढ़ दशक से महिलाओं के प्रति नजरिए में तेजी से बदलाव आया है जबकि चर्च से निर्देशित परंपरावादी इवेंजिलिस्ट रिपब्लिकन अपने पुराने ढर्रे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

दूसरी तरफ 78 वर्षीय ट्रंप के खिलाफ चार आपराधिक मामलों और करीब 92 अन्यान्य मामलों को लेकर डेमोक्रेट मतदाताओं में भी क्षोभ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 'इम्युनिटी' उपहार मिलने के बाद वह सहज स्थिति में हैं। वह प्रतिद्वंद्वी बाइडेन को 'स्लीपी' और कमला हैरिस को निष्क्रय मानते हैं। 'अमेरिका ग्रेट अगेन' के लिए अपनी ट्रेड और व्यापार नीतियों से 'मेड इन अमेरिका' जैसे स्लोगन से अमेरिका में चीनी माल के आयात पर अंकुश लगाना चाहते हैं। उन्होंने भारत और चीन में अमेरिकी कंपनियों के लिये आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कहकर एशियाई अमेरिकी मतदाता वर्ग समूह को नाराज किया है। इसका असर भारतीय और चीनी समुदाय पड़ा है। वहीं पड़ोसी देश मैक्सिको और लैटिन अमेरिकी देश इमिग्रेशन पर कड़ी कार्रवाई को लेकर पहले से दुखी हैं। असल में ट्रंप अपने 85 प्रतिशत कंजर्वेटिव (इवेंजिलिस्ट) ईसाई समुदाय वोट . बैंक पर निर्भर हैं जबकि अश्वेत मैक्सिकन और दस से चौदह प्रतिशत एशियाई वोट बैंक बटोर लेते हैं। पिछले एक माह में करीब एक दर्जन पोल सर्वे में कमला हैरिस और ट्रंप अथवा जो बाइडेन के बीच मात्र डेढ़ से दो प्रतिशत अंकों का अंतर दिखाया गया है। कमला हैरिस ट्रंप से आयु में बीस वर्ष कम, अधिक शिक्षित और कैलिफोर्निया की एक सुलझी हुई अटार्नी जनरल होने के नाते इस अंतर को दूर करने में सक्षम है। कमला हैरिस अपने वरिष्ठ सहयोगी और राष्ट्रपति जो बाइडेन से भले ही उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और देश की सामरिक और विदेश नीति में पारंगत होने के फलस्वरूप ज्यादा योग्य और सक्षम हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जो बाइडेन ही उन्हें अश्वेत, लैटिन अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी वोट बैंक को लुभाने के लिए उप राष्ट्रपति बनाकर लाए थे। इसीलिए उन्होंने पद की उम्मीदवारी से हटने के साथ कमला हैरिस को समर्थन दिया है। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक, ट्रेड और व्यापार संबंधी नीतियों का भारतीय अमेरिकी मतदाताओं पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन से बढ़ते आयात और घटते निर्यात की पृष्ठभूमि में दस से बीस प्रतिशत सीमा शुल्क लगाकर चीनी कंपनियों को निरुत्साहित किया था। इससे दोनों देशों के बीच पारस्परिक में संबंधों में दरार आ गई थी। इस बार ट्रम्प व्हाइट हाउस प्रवेश करते हैं और मध्य एशिया में इजराइल के चहेते अमेरिका में अपने धन कुबेर व्यवसाइयों से रिश्ते प्रगाढ़ करते हैं, तो मुमकिन है इजराइल और फि लिस्तीन युद्ध और आगे खिंच जाए।

अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव परोक्ष नियमावली से होते हैं, जिसके लिए पार्टियां चुनाव आयोग के सहयोग से विधान के मुताबिक निर्वाचक मंडल का गठन करती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दोनों सदनों में सीनेट के अवकाश प्राप्त करने वाले एक तिहाई और प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्यों का चुनाव भी इसी दिन (5 नवंबर) को होता है। इस बार इन चुनावों पर भारत और चीन सहित दुनिया भर की निगाहें लगी हैं।

कमला हैरिस के सम्मुख बड़ी अड़चनों में सबसे पहले भारती ड्ड नामांकन, पार्टी के राज्य और केंद्र स्तर पर नेताओं और मैक्सि ड्ड चुनाव प्रचार के लिए एक बड़े फंड के साथ ही जो बाइडेन कार्र के अपने 56 प्रतिशत वोट बैंक में एक विश्वास पैदा किए 85 जाने की जरूरत है। हांलाकि बाइडेन पहले ही कमला हैरिस बैंक का समर्थन कर चुके हैं। भारतीय अमेरिकी, अश्वेत तथा चोट अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी वोट बैंक ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप के पक्षपाती रवैये से बहुत आहत है। एशियन अमेरिकन एडवांसिंग जस्टिस के एक ताजा सर्वे में कहा गया है कि जो बाइडेन के चार साल पहले 56 प्रतिशत वोट में से मात्र 8 क प्रतिशत वोट ही उनसे छिटका है, शेष किसी भी स्थिति में न रिपब्लिकन की झोली में नहीं जाएगा। इसी सर्वे में ट्रंप को से एशियन अमेरिकी समुदाय के 25 से 31 प्रतिशत मत मिलने ल की संभावना जताई गई थी। इसमें भारतीय अमेरिकी कुल के जनसंख्या का मात्र 1.5 प्रतिशत ही हैं। एशियन अमेरिकन फ में सबसे तेज बढ़ता हुआ समूह है इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि , हुई है। इनमें से ज्यादातर मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट ले देंगे। इनमें 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता एशियन थ अमेरिकन है, जिनमें से 68 प्रतिशत युवाओं के मतदान करने की बात कही जा रही है। इस मतदाता वर्ग के सामने मुख्य मुद्दे रोजगार, हेल्थ और मेडिकेयर, मंहगाई और मकानों का बढ़ता किराया है। इन मुद्दों को कमला हैरिस पुरजोर तरीके से उठाती रही हैं, इस कारण भी इस वर्ग में उनके प्रशंसक ज्यादा हैं।

'मैं गर्व से खुद को पहाड़न कहती हूं'

मुंबई। अभिनेत्री रुबीना दिलैक ने कहा कि वह गर्व से खुद को 'पहाड़न' कहती हैं और उन्हें अपनी परंपराओं पर नाज है. शिमला की रहने वाली रुबीना ने इंस्टाग्राम पर अपने गृहनगर में हुई एक शादी की तस्वीरें शेयर कर पहाड़ी परंपरा से जुड़ाव की कहानी साझा की। तस्वीरों में उन्हें अपने परिवार के साथ पारंपरिक "हिमाचली" डांस करते हुए देखा जा सकता है। अपनी जड़ों पर गर्व करते हुए रुबीना ने लिखा, "मेरा हमेशा अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव रहा है, और मैं गर्व से खुद को पहाड़न कहती हूं।"

अभिनेत्री ने पारिवारिक समारोह से कुछ क्लोज-अप तस्वीरें भी शेयर कीं इसके लिए रुबीना ने कैप्शन में लिखा, "जुलाई में शादी।" रुबीना ने अभिनेता अभिनव शुक्ला से शादी की है। 34 वर्षीय अभिनेत्री दो बच्चों की मां हैं। उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट से ग्लैमर की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की। वह दो स्थानीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत चुकीं हैं। उन्होंने 2006 में मिस शिमला का खिताब अपने नाम किया था। रुबीना ने टीवी में 'छोटी बहू' से अपने अभिनय करियर की शुरूआत की, जो उनके लिए एक सफल शो साबित हुआ. इसके बाद वह 'सास बिना ससुराल', 'पुनर्विवाह- एक नई उम्मीद', 'देवों के देव...महादेव' और 'जीनी और जूजू' जैसे शो में काम करती हुईं नजर आईं। छोटी बहू के बाद उनका दूसरा सबसे हिट शो 'शक्ति अस्तित्व के एहसास की' रहा। इसमें उन्होंने विवियन डीसेना के साथ एक ट्रांस महिला का किरदार निभाया था। अभिनेत्री ने 'बिग बॉस' के 14वें सीजन में भाग लिया जहां वह विजेता बनकर उभरीं। रुबीना ने 'फियर फैक्टरः खतरों के खिलाड़ी' के 12वें सीजन और 'झलक दिखला जा 10' में भी हिस्सा लिया। 2022 में उन्होंने 'अर्ध' से अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की, जिसमें राजपाल यादव और हितेन तेजवानी जैसे मंझे कलाकार उनके साथ थे।

हर बार गैर-बराबरी ने अपने लिए गुंजायश तलाशा

पिछली सदी की समाजवादी शब्दावली में कहा जाता था, अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब। अब गरीब अधिक गरीब भले न हो रहा हो, लेकिन अमीर जिस तेजी से ज्यादा अमीर होता जा रहा है, उससे फासला बहुत बढ़ गया है। बजट के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इस बजट में विषमता को कम करने का कोई उपाय नहीं दिखता। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत में इस समय विषमता जहां पहुंच गई है, उतनी तो ब्रिटिश काल में भी नहीं थी। शशि थरूर जब यह कह रहे थे, तो दरअसल वह दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किए गए एक शोध पत्र का हवाला दे रहे थे, जो अभी कुछ ही महीने पहले जारी हुआ है। इस शोध-पत्र के अनुसार, इसके पहले भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा गैर बराबरी 1930 में थी, जब देश की एक फीसदी आबादी के पास पहुंचने वाली आमदनी देश की कुल आमदनी का 20 फीसदी थी। बाद के दौर में इसमें गिरावट आ गई। मगर लगभग सौ साल बाद हम वहां पहुंच गए हैं, जहां देश के एक फीसदी अमीरों के पास पहुंचने वाली आमदनी 20 फीसदी की पिछली बुलंदी को भी पार कर गई है।

बात जब ब्रिटिश दौर की हो रही है, तो प्रसंगवश ब्रिटेन की ओर भी झांक लेते हैं। आर्थिक गैर-बराबरी वहां भी हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले दिनों आम चुनाव में जिस तरह वहां के लोगों ने लेबर पार्टी को भारी बहुमत दिया, उसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि लोग आर्थिक दबावों की वजह से आजिज आ गए थे। और अब जब लेबर पार्टी जीत गई है, तो उसके सांसद ही दबाव डाल रहे हैं कि सबसे पहले गैर-बराबरी दूर करो। पार्टी का पूरा अमला इसी में सिर खपा रहा है कि इस अफसाने को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। वैसे, भारत में भी आम चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे के संकेत अपने घोषणापत्र में दिए थे। मगर चुनावी माहौल में इस पर कोई विमर्श होने के बजाय मंगलसूत्र और भैंस खोल ले जाने जैसी चर्चाएं ही खबरों में छाई रहीं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने केंद्रीय बजट की अपनी समीक्षा में भारत की बढ़ती आर्थिक विषमता का जिक्र किया है। उनका कहना है कि आर्थिक नीतियों को इसे कम करने के तरीके खोजने चाहिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और नीति आयोग के संस्थापक उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने भी कुछ सप्ताह पहले कहा था कि अब गैरबराबरी को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की बढ़ती आर्थिक विषमता पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब से लेकर यूएनडीपी की रिपोर्टों में भी भारत को उन देशों में रखा गया है, जहां अमीर और गरीब के बीच का फासला सबसे ज्यादा है। यह ठीक है कि पिछले दो दशकों में भारत में अति दरिद्रता कुछ कम हुई है। मनरेगा या सीधे अनाज बांटने की योजनाओं ने भुखमरी वाली गरीबी को कम किया है, मगर अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है।

कुछ अर्थशास्त्री चेता रहे हैं कि ऐसा बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी के साथ एक और चेतावनी नत्थी हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धन के केंद्रीकरण व विषमता को और बढ़ा सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इसके साथ बढ़ती बेरोजगारी कभी भी विस्फोट का कारण बन सकती है।

बावजूद इसके कोई नहीं जानता कि इसका किया क्या जाए? पिछली एक सदी में अमीरों पर भारी टैक्स लगाने से लेकर, संपत्ति कर से लेकर उपभोग कर तक के प्रयोग हुए। हर बार गैर-बराबरी ने अपने लिए गुंजाइश तलाश ली। जहां ऐसे प्रयासों ने अर्थव्यवस्था की लय बिगाड़ी, वहां इसका नजला भी गरीबों पर ही गिरा। हम चाहें, तो ऐसा करने वालों की नीयत पर शक कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि जो अमीर थे, उन्होंने हर बार अपने लिए तमाम नियम-कायदों के बीच से रास्ते निकाल लिए। ठीक यहीं पर राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक प्राचीन कहावत को भी याद कर लेना चाहिए - यह एक स्वर्णिम नियम है, जिसके पास स्वर्ण है, उसके पास नियम है। आर्थिक विषमता को हमेशा के लिए सुला देने की खातिर साम्यवादी व्यवस्थाएं कायम की गईं, जो अपने ही अंतरविरोधों से चरमरा गईं। पिछली सदी तक दुनिया के पास समता को कायम करने और विषमता खत्म करने की कई विचारधाराएं थीं। मगर 21वीं सदी के आते-आते उनके महल खंडहर में बदल गए, जो अब लोगों को आकर्षित नहीं करते। जिन्हें समता कायम करने की ऐतिहासिक शक्तियां कहा जाता था, उन्हें अब कोई याद भी नहीं करता। पूरे इतिहास में किसी समस्या के सामने हम इतने असहाय कभी नहीं रहे।

भारत और ब्रिटेन ही क्यों, यह तो तकरीबन सारी दुनिया में हो रहा है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की कोई भी सालाना रिपोर्ट उठा लीजिए, आपको तकरीबन हर जगह विषमता बढ़ती दिखाई देगी। अमेरिका तक में यही हो रहा है। इसे लेकर पहला आंदोलन भी वहीं शुरू हुआ था - ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। मगर समय के साथ इसके सुर ठंडे पड़ गए। अब कई अमेरिकी अर्थशास्त्री इस विमर्श में सिर खपा रहे हैं कि बढ़ती आर्थिक गैरबराबरी को समस्या माना भी जाए या नहीं? बेशक, वहां समस्या वैसी है भी नहीं, जैसी भारत जैसे कुछ देशों में है। तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका समाधान आसान नहीं है। कुछ का तो कहना है कि दुनिया ने जो आर्थिक व्यवस्था अपनाई है, उसके कुएं में ही विषमता की भांग पड़ी है। आप कुछ भी कर लें, धन और संपत्ति का केंद्रीकरण लगातार बढ़ता ही जाएगा। पहले यह माना जाता था कि विश्व अर्थव्यवस्था को जब झटका लगता है, तब गैर-बराबरी अपने आप नीचे आ जाती है। यही प्लेग महामारी के समय हुआ था । यही पिछली सदी की पहली महा-आर्थिक मंदी के समय हुआ और यही दोनों विश्व युद्धों के बाद हुआ। मगर 21वीं सदी ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। 2008 के वित्तीय संकट के समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। बाद में, जब सब सामान्य हुआ, तो पता चला कि विषमता और बढ़ गई है। इसके बाद कोविड जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और बहुत से लोगों के सिर पर अन्न और भोजन का संकट मंडराने लगा था, तब भी कुछ लोगों की ही संपत्ति लगातार बढ़ रही थी। गैरबराबरी अब हर आपदा में अपने लिए अवसर तलाश लेती है।

डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के उम्र में काफी अंतर था। डिंपल बताती हैं, 'मैं शादी के वक्त एकदम नादान थी। मुझे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैं कितनी फिल्मी थी इसके बारे में क्या ही बताऊं'।

काफी कम उम्र में डिंपल बनी थीं राजेश खन्ना की दुल्हन

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया काफी कम उम्र में राजेश खन्ना की दुल्हन बन गई थीं। उन्हें राजेश खन्ना बतुर अभिनेता काफी पसंद थे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी शादी के बारे में कई दिलचस्प खुलासे किए। साथ ही साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में भी खुलकर बाते कीं।

डिंपल फिल्मी थीं

डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के उम्र में काफी अंतर था। डिंपल बताती हैं, 'मैं शादी के वक्त एकदम नादान थी। मुझे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैं कितनी फिल्मी थी इसके बारे में क्या ही बताऊं। शायद आपको भरोसा नहीं हो, लेकिन मुझे लगता था कि शादी के बाद राजेश खन्ना मुझे पहाड़ों पर ले जाएंगे और मेरे लिए गाना गाएंगे। मैं सच में यही मानती थी'।

दिल टूटा जब राजेश खन्ना ने नहीं गाया गाना

डिंपल कपाड़िया अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, 'मैंने वास्तव में सोचा था कि राजेश खन्ना जी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू गाना मेरे लिए गाएंगे। वे जब मुझे पहाड़ों पर ले जाएंगे तब हवा चलने लगेगी और वे मेरे लिए इस गाने को गुनगुनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन मेरा दिल टूटा था। मुझे सच में लगता था कि मेरे साथ यह सब होगा'।

डिंपल कापड़िया उसी चैट शो में अपनी और राजेश खन्ना की प्रेम कहानी के बारे में बातें करती हुई कहती हैं, ' मैं अपनी फिल्म 'बॉबी' के सिलसिले अहमदाबाद जा रही थी। राजेश भी उसी फ्लाइट में थे और किस्मत से वे मेरे बगल में बैठे। मैंने हिम्मत जुटा कर उनसे कहा वहां तो बहुत भीड़ होगी तो आप मेरा हाथ पक-ड़ोगे ना। उन्होंने कहा हां बिल्कुल। फिर मैंने फिल्मी स्टाइल में पूछा हमेशा के लिए। ऐसे हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी'।

किशोरकुमार और उनके मज़ेदार किस्से

सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूजिक डायरेक्शन से लेकर लिरिक्स राइटिंग हर काम में माहिर किशोर कुमार को उनके टैलेंट ही नहीं, बल्कि मजाकिया और मनमौजी स्वभाव के लिए भी जाना जाता है. आज उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर सुनाते हैं उनसे जुड़े ज़िदादिल और मस्तमौला अंदाज के कुछ दिलचस्प किस्से

बचपन में फटे बांस जैसी आवाज थी किशोर कुमार की

किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। इसके बावजूद वो सुरों के जादूगर कहलाए और करोड़ों दिलों पर राज किया। इस बारे में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बताया था कि बचपन में किशोर की आवाज बिलकुल फटे बांस जैसी थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया था. पैर में गहरा जख्म हो गया. तब किशोर कुमार 2-3 दिन तक रोते ही रह गए. बस उन दिनों के रोने में ही उनका गला साफ हो गया।

दुनिया उन्हें पागल कहती थी

एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते, ना ही आपके बंगले पर कोई आता है. तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? इस पर किशोर कुमार ने जो जवाब दिया, उसके लिए उन्हें पागल कहा जाने लगा। किशोर कुमार ने कहा, ह्यनहीं, मुझे बिलकुल अकेला नहीं लगता. मैंने अपने घर में लगे इन पेड़-पौधों से दोस्ती कर ली है। उनके नाम रखे हैं. मैं इनसे ही बातें करता हूं.ह्ल इन इंटरव्यू के बाद उस मैगजीन ने उन्हें ह्यमैड मैनह्ल नाम दे दिया. इस पट किशोर ने कहा था, ह्यदुनिया कहती है मैं पागल और मैं कहता हूं दुनिया पागल।

किशोर दा कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे

किशोर कुमार कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे. वो कुंदन लाल सहगल के फैन थे और उनकी ही तरह गाना चाहते थे. लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए उन्हें एक्टिंग करने को कहा। किशोर दा एक्टिंग के लिए सीरियस नहीं थे. उन्हें जब भी अशोक कुमार के कहने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो वो कोई बहाना बना कर एक्टिंग करने से बच जाते थे. एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई-भाई के लिए सीन शूट करना था। किशोर ने फिर से अपना पैंतरेबाजी शुरू कर दी. लेकिन इस दफा अशोक कुमार के सामने उनकी दाल नहीं गल पा रही थी तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और भागने लगे। पर अशोक कुमार भी अशोक कुमार थे, उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रख दिया और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं शूटिंग हो सकी।

जब देव आनंद को गाली देकर भाग गए किशोर दा

एक्टिंग से बचने के लिए किशोर दा ने क्या क्या पैंतरे किए हैं, उनके तो ढेरों किस्से हैं, लेकिन देव आनंद के साथ जो उन्होंने किया था, उसे लोग आज तक याद करते हैं। हुआ यूं था कि एक फिल्म में अशोक कुमार और देव आनंद साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के एक सीन के लिए कोई एक्टर चाहिए था तो अशोक कुमार ने किशोर से कहा कि ये सीन तुम कर दो। अशोक कुमार ने उन्हें सीन भी समझा दिया कि जैसे देव अन्दर आएगा, तुझे उसे खरी-खोटी सुनानी है. किशोर ने हां तो कह दिया। लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देव आनंद अंदर आए, किशोर कुमार ने उन्हें सच में गंदी गाली दे दी और भाग गए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रहे कि सीन अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन किशोर कुमार तो एक दो तीन हो गए।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com